सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 135, नई दिल्ली, मंगलवार, 14 मार्च 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 सतीश की मौत का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन
05 दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी पंजीकरण होगा आसान
08 सरकार ने 2024-25 तक रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य तय किया

आज का सुविचार

जिस व्यक्ति का मन का भाव सच्चा होता है, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है।

केंद्रीय मंत्री ने दिया 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बोले- UP भी अमेरिका जैसा बनेगा समृद्ध

संजय बाटला

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कानून व्यवस्था एवं विकास के पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उनकी तुलना भगवान श्रीकृष्ण से की है।

गोरखपुर। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का आदर्शस्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर और यहां बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से यह स्पष्ट है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध व सम्पन्न प्रदेश बनेगा।

गडकरी सोमवार को गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 18 परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसी बनाने की अपनी पूर्व बात को याद करते हुए कहा कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुनी बढ़ गई है। वर्ष 2024 के समाप्त होने तक उत्तर प्रदेश में पांच लाख करोड़ रुपये के रोड पर काम किया जाएगा।

केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्ण, निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की सिलसिलेवार विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी-योगी जी के नेतृत्व में यूपी की सड़कें जैसी होंगी और अच्छी सड़कों से उत्तर प्रदेश भी अमेरिका जैसा समृद्ध बनेगा।

उन्होंने कहा कि बाबा गोरक्षनाथ जी की इस पावन भूमि पर लोकार्पित और शिलान्यास हो रही इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत नेटवर्क नजर आ रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय सड़क, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। देश में मजबूती के साथ हाइवे निर्माण हो रहा है। गडकरी जी ने इसकी रफ्तार को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। दुनिया अचंभित है कि कैसे सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से उभरते हुए आगे बढ़ रही है। इसका आधार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है।

मोदी जी-गडकरी जी ने की है यूपी की भरपूर मदद

सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में यूपी की भरपूर मदद की है। गडकरी जी ने गत दिनों बलिया में सात हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी तो आज गोरखपुर में आकर 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में राज्य सरकार हर संभव सहयोग करने को संकल्पित है।

इन सड़कों का हुआ शिलान्यास

1- सोनौली-जंगल कौड़िया मार्ग, कुल लंबाई-80 किलोमीटर, लागत 2700 करोड़
2- ग्रीनफिल्ड गोरखपुर बाईपास का निर्माण, लंबाई-27 किमी, लागत-2100
3- बड़हलगंज-मेहरौना घाट टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, लंबाई-57 किमी, लागत-974 करोड़
4- महराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, लंबाई-40 किमी, लागत-809 करोड़
5- हड़िया चौराहे से करमैनी घाट तक टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, लंबाई-49 किमी, लागत-516 करोड़
6- बलरामपुर बाईपास टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, लंबाई-21 किमी, लागत 516 करोड़
7- शोहरतगढ़-उस्काबाजार टू लेन पेव्ड शोल्डर, लंबाई-33 किमी, लागत-510 करोड़
8- सिकरीगंज-बडहलगंज टू लेन पेव्ड शोल्डर, लंबाई-39 किमी, लागत 403 करोड़
9- छपिया-सिकरीगंज टू लेन पेव्डशोल्डर, लंबाई-35 किमी, लागत-307 करोड़
10- शोहरतगढ़ बाईपास, लंबाई-6 किमी, लागत-189 करोड़
11- गोरखपुर-आनंदनगर रेलखंड पर ओवरब्रिज का निर्माण लागत 66 करोड़
12- गिलौला बाईपास टू लेन पेव्ड शोल्डर, लंबाई-3.50 किमी, लागत 62 करोड़

इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण

1- मोहद्दीपुर-जंगलकौड़िया फोरलेन, लंबाई-18 किमी, लागत-323 करोड़
2- छावनी-छपिया टू लेन पेव्ड शोल्डर, लंबाई-55 किमी, लागत-281 करोड़।
3- भौराबारी से लेकर परतावल चौराहे तक सड़क, लंबाई-26 किमी, लागत-94 करोड़
4- बंगाली टोला से लेकर बरनहा पूरब पट्टी तक सड़क, लंबाई-19 किमी, लागत-70 करोड़
5- कुंई बाजार से लेकर गोला तक सड़क, लंबाई-9 किमी, लागत-70 करोड़
6- बभनान में सीसी पेवमेंट का निर्माण, लंबाई-380 मीटर, लागत-4 करोड़

इनसाइड

रोडवेज बसों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर यात्रा कर रहे लोग

झांसी। परिवहन निगम द्वारा रोडवेज बसों में दिव्यांगों को यात्रा में रियायत दी जाती है। इसका लाभ उठाते हुए तमाम लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे बसों में यात्रा करते पाए जा चुके हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए रोडवेज की ओर से प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो योजनाओं का गलत लाभ उठा रहे हैं। पहले सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर ही दिव्यांग यात्रा करते थे। लेकिन इनकी पहचान न हो पाने की वजह से कई लोग फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर फ्री यात्रा का लाभ ले लेते थे और रोडवेज को राजस्व का नुकसान होता था। बीते तीन माह में 72 से ज्यादा मामले पकड़े थे, जो फर्जी कार्ड पर यात्रा कर रहे थे। अब विभाग ने इन कार्डों की जांच के लिए विकलांग व स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। उधर, सेवा प्रबंधक संतोष कुमार के मुताबिक परिचालकों को फर्जी प्रमाणपत्र का शक होने पर उनकी फोटो खींच ली जाती है, उसके बाद उनको जांच के लिए भेजा जाता है।

इस साल 45 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को मिलेगा रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर काम शुरू

प्रदेश में 45 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को इस साल दिसंबर तक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 2.83 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक परिवार की महिला को औसतन मासिक सात से आठ हजार रुपये की आय अर्जित कराने का लक्ष्य है। प्रदेश में मिशन के तहत 6.93 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। प्रत्येक समूह में 11 महिला सदस्य होत हैं। प्रदेश में कुल 72 लाख महिलाएं समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने वर्तमान वर्ष में 2.83 लाख नए समूह गठित करने और 45 लाख परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया है।

कर्नाटक: इलेक्ट्रिक स्कूटर में विस्फोट, बाल-बाल बचे परिवार के लोग

कर्नाटक के मांड्या जिले में एक परिवार के 5 लोग उस समय बाल-बाल बच गए, जब उनके घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाका हो गया। इस धमाके में कई घरेलू सामान और उपकरण जल गए हैं।

परिवार के पास रूट इलेक्ट्रिक कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर था, जो घर में चार्ज हो रहा था। स्कूटर को जब चार्जिंग के लिए प्लग में लगाया गया तो उसके कुछ ही मिनटों में इसमें धमाका हो गया।

6 महीने पहले शोरूम से खरीदा था स्कूटर

स्कूटर के मालिक का नाम मुथुराज है। मुथुराज कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दूर तालुका के वलागेरेहल्ली गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने लगभग 6 महीने पहले मांड्या के एक शोरूम से 85,000 रुपये में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था।

स्कूटर को चार्ज करने के लिए मुथुराज सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे घर के अंदर ले गए। चार्जिंग में लगाने के कुछ ही मिनटों में इसकी बैटरी फट गई और स्कूटर आग की लपटों से घिर गया।

धमाके से घर का टीवी, फ्रिज, मोबाइल जलकर खाक हुआ

स्कूटर की बैटरी फटने के वक्त घर में मौजूद 5 लोग स्कूटर से दूर थे। धमाके में घर का टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, मोबाइल और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है।

मुथुराज ने कहा, ₹दुर्घटना के समय मेरे परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। स्कूटर में आग के वक्त उसके पास एक बच्चा खड़ा था। हम आग पर काबू नहीं पा सके।₹

उन्होंने कहा कि घटना में 2-3 मोबाइल फोन जल गए और घर के शीशे टूट गए।

पहले भी हुई थीं ऐसी घटनाएं

ओला, ओकिनावा, प्योर ईवी, जितेंद्र इलेक्ट्रिक सहित कुछ अन्य कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में पहले भी आग लगने की कई घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं में जानमाल का भी नुकसान हुआ था।

आग लगने की घटनाओं पर सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी देते हुए वाहन निर्माता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को जांच के आदेश भी दिए थे।

बैटरी के लिए पेश किए BIS मानक

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी गई जांच में DRDO के सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी (CFEES) ने पाया कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता 'लागत में कटौती' के लिए बैटरी पैक के खराब डिजाइन और मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं।

रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने EV में बैटरी डिजाइन और गुणवत्ता-केंद्रित BIS मानक पेश किए थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के लिए BIS मानक चिह्न अनिवार्य होता है। ये गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करते हैं।

इन बातों का ध्यान रखने की सलाह देती हैं कंपनियां

कंपनी द्वारा यह सलाह दी जाती है कि कभी भी अपनी बैटरी का चार्ज कम ना होने दें। यह बैटरी और स्कूटर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।

वहीं, तेज धूप और बारिश के संपर्क में आने से बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसे खुले में पार्क करने से बचें।

यदि आपका स्कूटर तीन सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा रहा है तो सुनिश्चित करें कि 50 प्रतिशत बैटरी चार्ज बनाए रखें।

अस्पताल-बिल पेमेंट- नहीं - तो शव नहीं गैरकानूनी

एस.ठी सेठी

एनटीवी। बिल न चुकाए जाने पर अस्पताल मृतक की डेड बॉडी को देने से इन्कार नहीं कर सकते है। राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने पूछे गए एक सवाल पर खुलासा किया और कहा कि (क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट) 2010 के तहत एक वैधानिक संस्था नैशनल कौंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, द्वारा स्वीकृत द पेशेंट्स राइट चार्टर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।उक्त चार्टर के दिशा निर्देश के मुताबिकभारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 के तहत शव को बंधक बना कर रखना अपराध है। अस्पताल द्वारा किसी भी कारण से किसी रोगी के मृत शरीर को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।उपरोक्त चार्टर को अपनाने और लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सांझा किया गया है। ताकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में सुचारू और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हुए रोगियों की शिकायतों और चिंताओ को दूर किया जा सके। राज्य और यूनियन टरिटरी (यूटी) सरकारें अस्पतालों द्वारा शौषण की घटनाओ से मृतक के परिवार को बचाने के लिए उचित कदम उठाती है। इसी बावत पेशेंट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और नेशनल कौसिल फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा अप्रूवल और 23 अगस्त 2021 को अपडेट किया गया है। इस निर्देश को सभी अस्पतालों में ठीक से प्रदर्शित किया जाए। ताकि अस्पतालों द्वारा मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। अस्पताल द्वारा मृतक के शव को बंधक बनाकर रोकना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 के तहत गलत तरीके से बंधक बनाना परिभाषित होगा।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

यात्री बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे, तो बस का ड्राइवर नशे की हालत में था और बस तेज रफ्तार से चला रहा था।

दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर हादसा: श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर आज सोमवार सुबह सवेरे बड़ा हादसा हो गया। रोहद गांव के पास तीर्थ यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अचानक पलट गई। इस हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है।

हरियाणा। सभी घायलों को बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। जिनमें से 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है।घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं।

सभी घायल दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी श्रद्धालु राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करके राजधानी दिल्ली लौट रहे थे।बस में सवार लोगों ने बताया कि वे कल रविवार सुबह 10 बजे राजधानी दिल्ली के रावल नगर क्षेत्र स्थित सिग्नेचर ब्रिज के पास से बस में सवार होकर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले थे। यह भी पढ़ें...

नशे की हालत में था ड्राइवर

यात्री बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे, तो बस का ड्राइवर नशे की हालत में था और बस तेज रफ्तार से चला रहा था। जब बस दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित रोहद गांव के पास पहुंची तो बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

घायलों का इलाज बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में चल रहा

इस हादसे में करीब 35 लोग घायल हो गए हैं। जिनमें से पांच की हालत नाजुक बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। जबकि अन्य लोगों का इलाज बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है।

घायलों में ये लोग हैं शामिल

हादसे की मुख्य वजह ड्राइवर का नशे की हालत में होना और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना बताया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के बाद फरार हुए ड्राइवर की तलाश में जुट गई। घायलों में सुनील, मीनाक्षी, शालू, सुधा, विशाल, सोनी, सरोज द्रवइ, आशा, एक साल की कुशानी, गौरव, किशन कुमार, राम सागर, डोली, चवनलाल, दीपक, मीतू, भूषण राजेन्द्र, ओमपति, जतिन, मुन्ना लाल, दीपक, ध्रुप, चांद, राजेश, रवींद्र, अकास, सुमित, विपिन, निखिल, निशा गर्वती, रवि, तेजपाल, रोमी व रोहित

इनसाइड

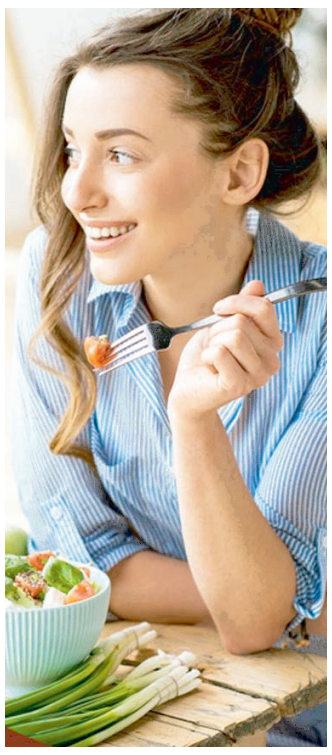

काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बढ़ रहा है वजन, महिलाएं फॉलो करें ये टिप्स, तेजी से होगा वेट गेन

दुबली-पतली महिलाएं आमतौर पर वेट गेन करने के लिए अनगिनत नुस्खे आजमाती हैं, मगर हेल्दी डाइट फॉलो करने के बावजूद भी कई बार वजन नहीं बढ़ पाता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन महिलाओं के लिए बेस्ट हो सकता है.

स्लिम एंड ट्रिम लुक कैरी करने के लिए महिलाएं कई तरीके अपनाती हैं. इसके बावजूद कुछ महिलाएं मोटापे का शिकार होने लगती हैं. तो वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, जो अपने दुबलेपन को लेकर परेशान रहती हैं. अगर आपका वजन काफी कम है तो कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इन चीजों को डाइट में शामिल करके आप आसानी से वेट गेन (Weight gain tips) कर सकती हैं.

पतली और दुबली महिलाएं अक्सर अपने फिगर को लेकर टेंशन में रहती हैं. वहीं पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने के बाद भी कई बार महिलाओं का वजन बढ़ने का नाम नहीं लेता है. ऐसे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का सेवन आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है. तो आइए ओन्लीमाईहेल्थ डॉट कॉम के अनुसार, जानते हैं वजन बढ़ाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके महिलाएं खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

प्रोटीन का सेवन करें

नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन को बॉडी का बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है. खासकर प्लांट बेस्ड प्रोटीन में शुगर और फैट भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है, जिससे मसल्स बिल्डिंग में काफी मदद मिलती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है. ऐसे में आप पनीर, फुल क्रीम मिल्क, दही और दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में शामिल कर सकती हैं. साथ ही चिकन, अंडा, लाल मीट, मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर जैसी चीजों से आप आसानी से वेट गेन कर सकती हैं.

फैट रिच डाइट लें

वजन बढ़ाने के लिए महिलाएं फैट से भरपूर चीजों को भी डाइट में एड कर सकती हैं. ऐसे में घी, मक्खन, नट्स और गुड फैट से भरपूर चीजों का सेवन करना महिलाओं के लिए बेस्ट होता है. इससे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है और महिलाओं के वजन में भी इजाफा देखने को मिलने लगता है.

कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें खाएं

कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें बॉडी में कैलोरी इन टेक को बढ़ावा देती हैं. जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में वेट गेन करने के लिए महिलाएं आलू, शकरकंद, ओट्स, ग्रेन और ब्राउन राइस का सेवन कर सकती हैं. वहीं घी और बटर से युक्त चीजें खाने से भी वेट गेन फास्ट होने लगता है.

वजन ना बढ़ने के कारण

महिलाओं में वजन ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. दरअसल कई बार महिलाओं के शरीर में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते हेल्दी डाइट लेने के बावजूद महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है और उनका वजन कम रहता है. इसके अलावा इंफ्लेमेटरी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और हाइपोथायरॉयडिजम के चलते भी महिलाओं का वजन नहीं बढ़ता है।

भारत की 5 महिला खिलाड़ी, जीवन के संघर्षों से कभी नहीं मानी हार, आज दुनिया मानती है लोहा

महिलाओं का दबदबा खेल जगत में भी बढ़ा है. भारतीय खेल के इतिहास में कई ऐसी महिलाएं युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हैं, जिन्होंने तमाम परिस्थितियों के बावजूद देश का परचम दुनियाभर में फैलाया है. आज कई भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. उनकी रैंकिंग भी दुनिया की टॉप खिलाड़ियों में शामिल हो गई है. जिन खेलों में अब तक पुरुषों का दबदबा था, वहां भी महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है. 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' पर जानते हैं देश की नामी महिला खेलाड़ियों के संघर्षपूर्ण अचीवमेंट के बारे में.

विश्व महिला क्रिकेट में झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) की उपलब्धियां कम नहीं हैं. उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 से ज्यादा ओवर लेने वाली दुनिया की इकलौती गेंदबाज हैं. कभी ऐसा था कि गली क्रिकेट में उनकी धीमी गेंदबाजी पर मोहल्ले के लड़के चौके-छक्के लगाया करते थे, लेकिन झूलन ने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मेहनत किया और आज उनके नाम इतने खिताब हैं. बता दें कि उन्होंने कुल 333 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं. (Image: Jhulan Goswami-Instagram)

2/5 भारतीय मुक्केबाद जमुना बोरो (Jamuna Boro) असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गाँव से ताल्लुख रखती हैं. बचपन में ही बोरो के के पिता का निधन हो गया और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अकेली मां खेती और चाय व सब्जियां बेचा करती थीं. छोटी जमुना बचपन में ही मुक्केबाद बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने मनोबल गिराने वाली कई बातें कहीं. लेनिक जमुना ने हार नहीं माना और मुक्के बा जी को ही अपना क रि य र बनाया. आज जमुना बोरो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नम्बर एक मुक्केबाज हैं और विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल रह चुकी हैं. उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है.

भारतीय मुक्केबाद जमुना बोरो (Jamuna Boro) असम के छोटे से कस्बे ढेकियाजुली के पास बेलसिरी गाँव से ताल्लुख रखती हैं. बचपन में ही बोरो के के पिता का निधन हो गया और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए अकेली मां खेती और चाय व सब्जियां बेचा करती थीं. छोटी जमुना बचपन में ही मुक्केबाद बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने मनोबल गिराने वाली कई बातें कहीं. लेनिक जमुना ने हार नहीं माना और मुक्केबाजी को ही अपना करियर बनाया. आज जमुना बोरो 54 किलोग्राम वर्ग में भारत की नम्बर एक मुक्केबाज हैं और विश्व रैंक में जमुना टॉप 5 में शामिल रह चुकी हैं. उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेडल जीता है.

3/5 भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. केरल में जन्मी अंजू को बचपन से ही उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीते. साल 2003 में पेरिस में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में जब अंजू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो पूरा देश हतप्रभ था. वह भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं. (Image : Anju Bobby George-Instagram)

भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज (Anju Bobby George) विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं. केरल में जन्मी अंजू को बचपन से ही उनके माता पिता को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीते. साल 2003 में पेरिस में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में जब अंजू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता, तो पूरा देश हतप्रभ था. वह भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं.

4/5 असम के नागौड जिले की एथलीट हिमा दास (Hima Das) को आज कौन नहीं जानता. छोटे कद की इस भारतीय धाविका ने दुनियाभर को चौंका दिया था. महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी पुरुष खिलाड़ी के लिए भी आसान नहीं था. बता दें कि हिमा दास के परिवार में 17 लोग थे जो धान की खेती पर आश्रित थे. वह परिवार की मदद के लिए खेतों में बुआई करती थीं, लेकिन जब उनको उड़ने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी किसी के हुनर को नहीं छीन सकती. हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की.

असम के नागौड जिले की एथलीट हिमा दास (Hima Das) को आज कौन नहीं जानता. छोटे कद की इस भारतीय धाविका ने दुनियाभर को चौंका दिया था. महज 20 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी पुरुष खिलाड़ी के लिए भी आसान नहीं था. बता दें कि हिमा दास के परिवार में 17 लोग थे जो धान की खेती पर आश्रित थे. वह परिवार की मदद के लिए खेतों में बुआई करती थीं, लेकिन जब उनको उड़ने का मौका मिला तो उन्होंने दिखा दिया है कि गरीबी किसी के हुनर को नहीं छीन सकती. हिमा पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते और आईएएएफ विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि हासिल की.

5/5 भारतीय महिला खिलाड़ियों में मैरी कॉम (MC Mary Kom) का नाम कई उपलब्धियों से भरा है. खिलाड़ी ही नहीं, वो महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा श्रोत हैं. महान भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम ने महान उपलब्धियों से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है. मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है. तीन बच्चों की मां रहते हुए भी उन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया. Image : Mary Kom Instagram

भारतीय महिला खिलाड़ियों में मैरी कॉम (MC Mary Kom) का नाम कई उपलब्धियों से भरा है. खिलाड़ी ही नहीं, वो महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा श्रोत हैं. महान भारतीय खिलाड़ी मेरी कॉम ने महान उपलब्धियों से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है. मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है. तीन बच्चों की मां रहते हुए भी उन्होंने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया.

कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक टेक्नीक से बाल-बाल बची ब्रिटनी विलियम्स की जान, अपनी स्टोरी शेयर कर कही, ना करें 2 संकेतों को इग्नोर

कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है.कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर तुरंत दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है.

आज लोगों में कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं. कम उम्र में ही पुरुष हों या महिलाएं, हर कोई हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो रहा है. कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों को समय पर ना पहचान पाने के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. हालांकि, ब्राजील की रहने वाली ब्रिटनी विलियम्स नाम की महिला की किस्मत इस मामले में अच्छी साबित हुई थी. मात्र 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था. वह अचानक बेहोश हो गई थीं और आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. दो दिनों के बाद जब उन्हें होश आया तो पता चला कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था.

टूडे डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, मात्र 24 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण ब्रिटनी विलियम्स की जान जाने ही वाली थी. यह घटना वर्ष 2014 की है. पूरे 9 वर्ष बाद ब्रिटनी ने अपनी कार्डियक अरेस्ट के दौरान हुई स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित जानकारी टुडे शो में एक इंटरव्यू के दौरान साझा की है. ब्रिटनी ने शो में उन लक्षणों के बारे में भी बताया, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज़ कर दिया था. जब ब्रिटनी को कार्डियक अरेस्ट आया था, तो उस दौरान उन्हें कोई भी लक्षण महसूस नहीं हुए. अचानक वो बेहोश हो गईं. इंटरव्यू में वो बताती हैं कि यदि उन्हें तुरंत वहां मौजूद लोगों ने सीपीआर ना दिया होता तो आज वो जिंदा नहीं होती. ब्रिटनी ने शो में सीपीआर ट्रेनिंग लेने के महत्व पर भी जोर दिया.

कार्डियक अरेस्ट के संकेत

कार्डिएक अरेस्ट तब होता है, जब एलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण हृदय की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं, जिससे दिल का धड़कना अचानक बंद हो जाता है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (यूएस) के अनुसार, लगभग 90% लोग जिन्हें हॉस्पिटल के बाहर कार्डियक अरेस्ट आता है, उनकी मौत हो जाती है. यदि सही समय पर पीड़ित को सीपीआर दे दिया जाए तो काफी हद तक जान बचाई जा सकती है. इसके लिए सीपीआर देने के बाद तुरंत ही दिल को सामान्य लय में वापस लाने के लिए डिफाइब्रिलेटर का उपयोग भी करना चाहिए. लोग अक्सर हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक समझने की गलती कर बैठते हैं. हार्ट अटैक तब आता है, जब हार्ट में ब्लॉकेज हो. हालांकि, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बिना किसी वॉर्निंग साइन के आ सकता है. लेकिन, ब्रिटनी ने कुछ लक्षणों को इग्नोर करने की भूल की जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने से पहले महसूस हुए थे.

ब्रिटनी ने किया इन लक्षणों को नजरअंदाज

ब्रिटनी ने इंटरव्यू में कहा कि जब वह काम पर थीं, तब शरीर के बाईं ओर सुन्नपन, झुनझुनी और सनसनी जैसे लक्षणों को महसूस किया था. इलाज करने के बाद पता चला कि ब्रिटनी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम (QT syndrome) से ग्रस्त थीं. यह एक ऐसी समस्या है, जिसमें हार्टबीट तेज और अनियमित हो जाता है. अधिकतर लोग लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं. कई बार यह दवाओं के कारण भी हो सकता है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार इसे सीजर (seizure) या मिर्गी समझ लिया जाता है. इसका इलाज दवाओं और जीवनशैली में बदलाव लाकर किया जाता है.

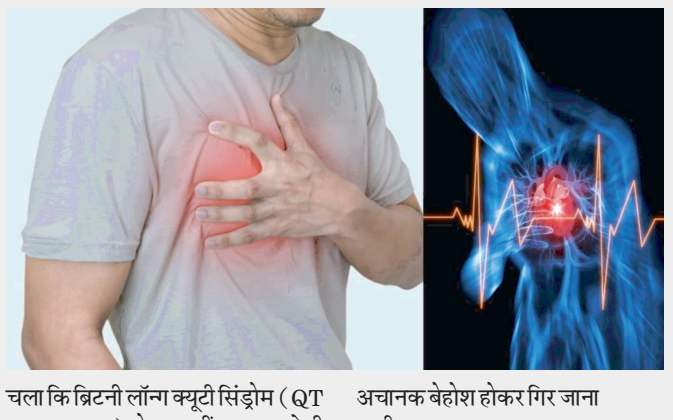

कार्डियक अरेस्ट के कॉमन लक्षण

अचानक बेहोश होकर गिर जाना
नाड़ी का रुक जाना
सांस का रुकना
कार्डियक अरेस्ट आने से पहले सीने में तकलीफ
सांस लेने में तकलीफ महसूस करना
कमजोरी महसूस करना
दिल का तेजी से धड़कना

इस तरह के लक्षण यदि आपको कभी भी नजर आएं, तो भूलकर भी इग्नोर ना करें. ये कार्डियक अरेस्ट आने से पहले के संकेत हो सकते हैं. अक्सर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जैसा कि ब्रिटनी के मामले में हुआ. ब्रिटनी ने भी कार्डियक अरेस्ट आने से पहले शरीर में सुन्नपन, झुनझुनी या सनसनी जैसे लक्षण महसूस किए थे, लेकिन उसने लोगों की कही हुई बातों के आधार पर इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ कर दिया था.

कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर का महत्व

जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो बहुत जरूरी है कि उसके पास तुरंत कोई मेडिकल हेल्प पहुंच जाए. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर (CPR) ऐसे में लाभ पहुंचाता है. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हार्ट को कम्प्रेशन देकर एक विद्युत आवेग बनाने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय दोबारा से पंप करने लगता है. ऐसे में आज हर किसी को सीपीआर देने की टेक्नीक को सीखना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप पीड़ित की जान बचाने में सफल हो सकें. ब्रिटनी विलियम्स भी अब कुछ ऐसा ही करने में जुटी हुई हैं, ताकि उन्हीं की तरह दूसरे लोगों की भी जान बच सके.

इनसाइड

भाजपा बोली- मास्टर माइंड भी नहीं बचेगा, AAP ने कहा- जारी रहेगा विरोध

आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया के हिरासत में जाने के बाद ज्यादा आक्रामक रूख अपनाने के संकेत किए हैं। पार्टी ने कहा है कि अदाणी मामले में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं, लेकिन उन्हें एक नोटिस तक नहीं दिया गया, जबकि आम आदमी पार्टी को पूछताछ के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है...

नईदिल्ली। मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे जाने पर भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा ने कहा है कि पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेजे जाने से यह साबित हो गया है कि अदालत भी मानती है कि इस मामले में ज्यादा पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है। भाजपा ने कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया के भी जेल के पीछे जाने से अरविंद केजरीवाल सरकार के एक तिहाई मंत्री जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

भाजपा ने कहा है कि यदि आम आदमी पार्टी को यह लग रहा था कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, तो उसे इसके खिलाफ अदालत में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन उसने यह नहीं किया। इससे भी साबित होता है कि आम आदमी पार्टी इस मामले में कोर्ट जाने से बचना चाहती थी। भाजपा ने कहा है कि हर भ्रष्टाचारी को कानून की जांच से होकर गुजरना पड़ेगा। पार्टी ने कहा है कि इस मामले का जो भी मास्टर माइंड होगा, वह भी ज्यादा देर तक कानून से बच नहीं पाएगा।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया के हिरासत में जाने के बाद ज्यादा आक्रामक रूख अपनाने के संकेत किए हैं। पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले की जांच के कारण नहीं हुई है, बल्कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि अदाणी मामले में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले हुए हैं, लेकिन उन्हें एक नोटिस तक नहीं दिया गया, जबकि आम आदमी पार्टी को पूछताछ के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है।

डराने की कोशिश

सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। यदि एक्साइज पॉलिसी की जांच हो रही होती, तो इस मामले में उपराज्यपाल की भूमिका की भी जांच होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लंबी जांच के बाद भी सीबीआई कोई सबूत नहीं खोज पाई थी। अब कोर्ट ने अदालत को पांच दिन का समय दिया है, लेकिन वह इन पांच दिनों में भी कोई सबूत नहीं खोज पाएगी। गोपाल राय ने कहा कि इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। शीघ्र ही वे एक नई रणनीति के साथ मैदान में आएंगे और पुरजोर तरीके से इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। आज भी पूरे दिन दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया।

भाजपा ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा

वहीं, भाजपा ने कहा है कि हर भ्रष्टाचारी को कानून का सामना करना पड़ेगा। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि मनीष सिसोदिया को पांच दिन की रिमांड में भेजे जाने का यह अर्थ है कि कोर्ट ने यह माना है कि इस मामले की पूरी जांच के लिए उनसे ज्यादा पूछताछ की आवश्यकता है। यह साबित करता है कि कोर्ट ने यह माना है कि प्राथमिक दृष्टि में इस मामले की जांच किए जाने के लिए पर्याप्त उचित कारण मौजूद हैं।

सतीश की मौत का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन

यहां हुई पार्टी में आया था दाउद इब्राहिम का बेटा!

एनटीवी संवाददाता

फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। विकास मालू की दूसरी पत्नी सान्वी ने शिकायत में सतीश कौशिक व विकास की एक तस्वीर साझा करने की बात कही है। महिला का आरोप है कि दुबई में हुई पार्टी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम का बेटा था।

नईदिल्ली। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक को जब सीने में दर्द हुआ तो वह पहली मंजिल पर स्थित कमरे में थे। दर्द होने पर वह पहली मंजिल से नीचे उतरकर खुद की पोर्चे गाड़ी में बैठे थे। यह खुलासा फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद हुआ है। कपासहेड़ा थाना पुलिस ने फार्म हाउस से सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को जब्त कर लिया है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए एक इंस्पेक्टर की देखरेख में आठ सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम ने रविवार को फार्म हाउस का दौरा किया था।

सतीश कौशिक का होली की पार्टी में डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह हिंदी गाने पर डांस करते हैं। उन्होंने सफेद कुर्ता-पजामा पहना हुआ है। इस वीडियो में कुछ लोग डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभिनेता ने पार्टी में करीब 45 मिनट डांस किया था।

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार होली की पार्टी में 20 से 22 लोग शामिल हुए थे। पार्टी तीन बजे खत्म हो गई थी। सभी लोग शाम पांच बजे तक फार्महाउस से अपने घर चले गए थे। सतीश कौशिक को रात 12.10 बजे सीने में दर्द हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर के सहारे वह खुद सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सतीश कौशिक के कमरे से डायजिन व पेट सफा की एक बोतल मिली हैं। इसके अलावा ब्लेड प्रेशर व शुगर की दवाइयां मिली हैं। हालांकि, ये दवाइयां उनके मैनेजर के पास रहती थीं। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि अभिनेता सतीश कौशिक एक फिल्म बनाने वाले थे। इस फिल्मी की डील के लिए वह विकास मालू से बात करने फार्म हाउस गए थे।

पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस राजीव कुमार व एसीपी वीकेपीएस यादव की टीम ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में जाकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी हैं।

विकास मालू ने आरोप को बताया बेबुनियाद

गंभीर आरोप लगाने के बाद विकास मालू ने चुप्पी तोड़ी है। विकास ने इंस्टाग्राम पर होली वाला वीडियो डालकर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विकास मालू ने सफाई दी है कि उनके व सतीश के बीच 30 वर्षों से पारिवारिक संबंध रहे हैं और लोगों को मेरे नाम पर कीचड़ उछालने में कुछ ही मिनट लगे। वह हर जश्न में सतीश कौशिक को मिस करेंगे।

पुलिस अंडरवर्ल्ड को लेकर जांच कर रही है

विकास मालू की दूसरी पत्नी सान्वी ने शिकायत में सतीश कौशिक व विकास की एक तस्वीर साझा करने की बात कही है। महिला का आरोप है कि दुबई में हुई पार्टी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम का बेटा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सान्वी व विकास के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है। ऐसे में पुलिस बदले की भावना से भी जांच कर रही है।

विकास मालू की पत्नी ने कमिश्नर को लिखा खत, जांच

विकास मालू की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विजय पर भष्ट होने के आरोप लगाए हैं। विकास मालू की पत्नी इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल कमिश्नर का बेहद खास अफसर बता रही हैं।

नई दिल्ली। विकास मालू की पत्नी ने सतीश कौशिक की मौत मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। विकास मालू की दूसरी पत्नी ने चिट्ठी में कापसहेड़ा थाने से अलग किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाने की बात लिखी है। दूसरी ओर पुलिस ने मालू की पत्नी को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है।

विकास की पत्नी ने जांच अधिकारी पर अपने रेप केस में सबूत नष्ट करने के लगाए आरोप

इसके साथ ही विकास मालू की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विजय पर भष्ट होने के आरोप लगाए हैं। विकास मालू की पत्नी इंस्पेक्टर को दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल कमिश्नर का बेहद खास अफसर बता रही हैं। उनका दावा है कि इसी अधिकारी ने उनके रेप केस में भी सबूत नष्ट किए थे। ऐसे में उन्होंने गुहार लगाई है कि वह जांच में जरूर शामिल होंगी लेकिन जांच अधिकारी को बदल दिया जाए।

पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस राजीव कुमार व एसीपी वीकेपीएस यादव की टीम ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में जाकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी हैं।

पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए विकास मालू की दूसरी पत्नी को बुलाएगी

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को मेल कर अभिनेता सतीश कौशिक की मौत पर सवाल उठाने वाली महिला के बयान दर्ज करेगी। महिला ने विकास व उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप था कि सतीश कौशिक व विकास के बीच 15 करोड़ रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद था। पुलिस जल्द ही महिला को नोटिस देकर बुलाएगी। इसके अलावा पुलिस पुष्पांजलि मालू फार्म हाउस के मालिक विकास मालू से पूछताछ करेगी। पुलिस उसे भी नोटिस देने जा रही है।

विकास मालू ने आरोप को बताया बेबुनियाद

गंभीर आरोप लगाने के बाद विकास मालू ने चुप्पी तोड़ी है। विकास ने इंस्टाग्राम पर होली वाला वीडियो डालकर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विकास मालू ने सफाई दी है कि उनके व सतीश के बीच 30 वर्षों से पारिवारिक संबंध रहे

'कौशिक जी के पैसे नहीं लौटाना चाहता था विकास, रशियन गर्ल और ब्लू पिल्स के ओवरडोज का था प्लान'

सान्वी ने बताया कि मैंने विकास से पूछा था ये सतीश कौशिक जी कौन से रुपये मांग रहे थे? इस पर विकास ने बताया, 'इसने 15 करोड़ रुपये दे रखे हैं, जो कोरोना काल में डूब गए।

नई दिल्ली। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खासतौर पर जब से सतीश के दोस्त विकास मालू की दूसरी पत्नी सान्वी मालू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिख, इस बात की शिकायत की है कि उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि एक हत्या है, जिसे मेरे पति ने किया है।

फार्महाउस में लगे सीसीटीवी की डीवीआर पुलिस के कब्जे में

सान्वी की लिखित शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने जांच के आदेश दिए। रविवार को पुलिस की एक टीम विकास मालू के फार्महाउस भी गई, जहां करीब 20-22 लोगों से पूछताछ की गई और वहां लगे सीसीटीवी की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है।

सान्वी ने बयान दर्ज कराने से किया इनकार

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सतीश कौशिक की मौत पर सवाल उठाने वाली महिला सान्वी मालू के बयान दर्ज करने के लिए उन्हें सोमवार को नोटिस भेजा गया है। हालांकि इस नोटिस के बाद सान्वी ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जिस अधिकारी को यह केस सौंपा गया है वह भ्रष्ट है। यह अधिकारी उनके साथ हुए दुष्कर्म के केस में सबूत नष्ट कर चुका है और इस मामले में भी ऐसा ही करेगा।

विकास ने कहा था ठरकी है सतीश, रशियन और ब्लू पिल्स की ओवर डोज दें देंगे

सान्वी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने एक जगह सतीश कौशिक और विकास के बीच 15 करोड़ रुपये के विवाद को लेकर जिक्र करते हुए बताया कि 23 अगस्त 2022 को सतीश कौशिक हमारे दुबई स्थित घर आए थे। इस दौरान उन्होंने विकास से अपने 15 करोड़ रुपए वापस मांगे। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहश भी हुई थी। बाद में विकास ने सतीश से उस दौरान वादा किया वह उनके 15 करोड़ जल्द ही भारत आकर देगा। रात को जब हम बेडरूम में थे तो मैंने विकास से पूछा था ये सतीश कौशिक जी कौन से रुपये मांग रहे थे? इस पर विकास ने बताया, 'इसने 15 करोड़ रुपये दे रखे हैं, जो कोरोना काल में डूब गए। फिर जब मैंने पूछा कि अब क्या करोगे? तो विकास ने कहा किसी दिन रशियन गर्ल बुलाकर, ब्लू पिल्स की ओवर डोज दे देंगे, तो वैसे ही मर जाएगा। इसे कौन रुपये वापस कर रहा है।

आरोप लगने के बाद विकास मालू ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो डाला

अपने ऊपर गंभीर आरोप लगाने के बाद विकास मालू ने चुप्पी तोड़ी है। विकास ने इंस्टाग्राम पर होली वाली वीडियो डालकर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विकास मालू ने सफाई दी है कि उनके व सतीश के बीच 30 वर्षों से पारिवारिक संबंध रहे हैं और लोगों को मेरे नाम पर कीचड़ उछालने में कुछ ही मिनट लगे। मैं सतीश कौशिक को हर जश्न में मिस करूंगा। विकास ने कहा कि उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने मैनेजर संतोष को लगभग 12:20 बजे कॉल किया और अस्पताल के लिए निकल गए लेकिन वे अस्पताल के गेट तक नहीं पहुंच सके। हम दोनों ने लगभग 9:15 बजे खाना खाया और सो गए। तब तक वह पूरी तरह से सामान्य थे।

'जासूसी कांड' में 'आप' की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, NIA करेगी मामले की जांच, एलजी ने लिया एक्शन

एनटीवी संवाददाता

एलजी कार्यालय से जानकारी दी गई है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, प्रोफेसर किरण वालिया के द्वारा जासूसी कांज की जांच यूएपीए के तहत एनआई से करवाने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली। जासूसी कांड को लेकर दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फीडबैक यूनिट की तरफ से नेताओं की जासूसी कराए जाने के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी एनआईए से जांच कराना चाहती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगत राम और किरण वालिया ने एलजी वीके सक्सेना से यूएपीए के तहत एनआईए से जांच कराने की मांग की है। मामले को मुख्य सचिव के पास भेजने के साथ ही एलजी ने एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।

एलजी कार्यालय से जानकारी दी गई है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल, प्रोफेसर किरण वालिया के द्वारा जासूसी की जांच यूएपीए के तहत एनआई से करवाने की मांग की गई थी।

जानिए क्या है पूरा मामला?

2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट (एफबीयू) बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहां के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके। लेकिन आरोप है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर इस फीडबैक यूनिट ने विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करनी शुरू कर दी। कई नेताओं के कामकाज पर नजर रखी जाने लगी।

आप ने आरोपों को झूठा बताया

इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने झूठ का पुलिंदा बताया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, 'अपने प्रतिद्वंदियों को झूठे केस में फंसाना कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे-जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे।'

सड़क हादसे में घायल के परिजनों को मिलेगा 1.81 लाख रुपये का मुआवजा

एनटीवी न्यूज

2019 में टिकरी गांव के पास पिकअप ने मारी थी मोटरसाइकिल को टक्कर

सुनवाई के दौरान घायल की मौत होने पर पत्नी व बेटे को मिलेगा मुआवजा

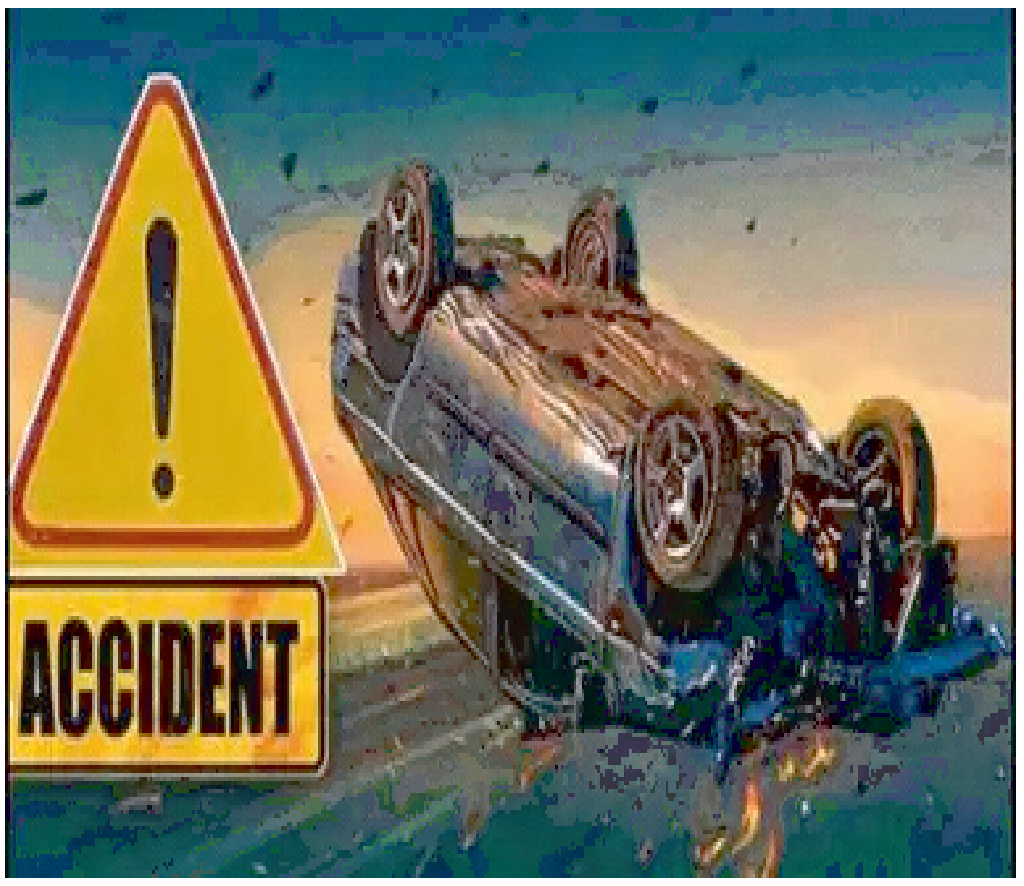

गुरुग्राम। 2019 में टिकरी गांव के पास पिकअप की टक्कर लगने से घायल के परिजनों को अदालत ने 1.81 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रताप की अदालत ने बीते शुक्रवार को दिए है। अदालत ने आदेश दिया है कि रुपये पिकअप चालक व उसके मालिक की तरफ से दिए जाएंगे। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ति मेहर चंद की मौत हो गई थी। इसलिए अब मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी सुनीता देवी व उसके बेटे सत्येंद्र सिंह को आधी-आधी दी जाए। यह राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।

26 जुलाई 2019 को टिकली निवासी महर चंद घर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान पिकअप चालक मनोहर लाल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल होकर सड़क पर ही गिर गए थे। घायल को उनके भतीजे ने अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी का काम करता था। उनकी शिकायत पर बादशाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर किया था।

घायल ने 20 लाख रुपये के मुआवजे के लिए 2022 में जिला अदालत में याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने फैसला देते हुए पिकअप चालक मनोहर लाल व पिकअप मालिक सत्यपाल सिंह को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिए है।

बीते हुए कल से अपने आज को बेहतर करें : मुक्केबाज मैरी कॉम

फिटनेस ड्राइव मेक योर मूव विद मैरी कॉम कार्यक्रम में मैरी कॉम को सम्मानित करते हुए।

फिटनेस ड्राइव मेक योर मूव विद मैरी कॉम कार्यक्रम में मैरी कॉम को सम्मानित करते हुए।

गुरुग्राम। महान मुक्केबाज, ओलंपिक विजेता पद्म विभूषण एमसी मैरी कॉम ने कहा कि हमें किसी और से बेहतर होने से पहले अपने बीते हुए कल से अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए संतुलित जीवन शैली और फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है।

छह बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम ने गुरुग्राम के इमैजिन ट्रेसर में फिटनेस ड्राइव मेक योर मूव विद मैरी कॉम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और फिट रहने के लाभों के विषय में बताना था। इस अवसर पर उद्यमिता और सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की 13 महिलाओं को उनके क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया। तरुण सेठ ने एमसी मैरी कॉम को सम्मानित किया।

मैरी कॉम की मणिपुर के एक छोटे से गांव से मुक्केबाजी की दुनिया में एक विश्व आइकॉन बनने तक की प्रेरक यात्रा ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत बना दिया। कार्यक्रम में रॉक बैंड ने भी प्रस्तुति दी। जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उनमें आयकर विभाग की अपर आयुक्त अमनप्रीत कौर, वाणिज्य मंत्रालय की स्टार्ट अप इंडिया हेड आस्था ग्रोवर, उद्यमी आंचल सैनी, रिद्धिमा अरोड़ा, दीया साहनी, डॉ. पायल कनोडिया, डॉ. सपना राकेश, रानी गर्ग, किरन बिष्ट, रचना गुप्ता, गायत्री सुब्रमण्यम, गरिमा धमीजा, लेखक परोमा भट्टाचार्य शामिल रहीं।

होटल का कमरा किराए पर लेकर 6 एलईडी चोरी की

एनटीवी न्यूज

लोनी। रामेश्वरपार्क कॉलोनी स्थित होटल से एक चोर ने 6 एलईडी चोरी कर ली। चोर ने शनिवार रात होटल का कमरा किराए पर लेकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सर्वेश धामा का रामेश्वरपार्क कॉलोनी में होटल है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 7 बजे बदायूं में रहने वाला एक व्यक्ति उनके होटल में कमरा लेने आया था। उसने होटल का रूम नंबर 101 लिया। अपनी आईडी और फोन नंबर भी जमा कराई। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह साढ़े 3 बजे चोर ने होटल के अलग-अलग 6 कमरों की एलईडी चोरी कर अपने कमरे में रख दी। इसके बाद उसने बेड पर पड़ी बेड सीट से उन्हें बांधा और पीछे के रास्ते से लेकर फरार हो गया। होटल स्टाफ को सुबह पता चला। उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है। एसीपी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है।

बुलंदशहर: आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक, महिला की मौत

एनटीवी न्यूज

बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में अनूपशहर बस अड्डे के निकट रविवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

नई दिल्ली। बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र में अनूपशहर बस अड्डे के निकट रविवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। जिसमें एक बाइक पर सवार महिला नीतू व उसके पति विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में चिकित्सकों ने नीतू को मृत घोषित कर दिया। जबकि, विपिन को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है।

जंगली जानवर का आतंक: हमले में वृद्ध की मौत, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल, वन विभाग और पुलिस टीम जांच में जुटी

एनटीवी न्यूज

सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी वृद्ध की मौत जंगली जानवर के हमले से होना सामने आ रहा है।

बुलंदशहर के अहार थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद ताहारपुर के जंगल में अपने खेत पर सो रहे वृद्ध पर रविवार देर रात अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार सुबह खेत पर पहुंचे परिजनों को मामले की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस व वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है।

गांव औरंगाबाद ताहारपुर निवासी 65 वर्षीय बसंता सिंह खेत पर ही अपने पशु बांधकर रहते थे। जबकि, परिवार के अन्य सदस्य गांव में रहते हैं। बताया गया कि रविवार शाम को भी बसंता खाना खाने के बाद अपने खेत पर चले गए थे। देर रात में ही अज्ञात जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। उनकी गर्दन, मुंह और पेट पर जानवर के द्वारा मांस नोंच लिया गया। सोमवार सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तो उनका शव चारपाई से कुछ दूरी पर जमीन पर लहुलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। जिसके बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में भी वृद्ध की मौत जंगली जानवर के हमले से होना सामने आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग की टीम को मामले की सूचना दी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

औरंगाबाद ताहारपुर व आस पास के गांवों में भी जंगली जानवर के हमले से वृद्ध की मौत के बाद से दहशत का माहौल है।

वन विभाग की टीम जंगल में कर रही जानवर की तलाश

आशंका जताई जा रही है कि वृद्ध हमला करने वाला जानवर तेंदुआ भी हो सकता है। या फिर कोई अन्य जानवर हो सकता है। वन विभाग की टीम जंगल में जानवर की तलाश में जुट गई है। खून के धब्बों और पंजों के निशान के आधार पर जानवर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है।

खेत पर सो रहे किसान की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवर के हमले में वृद्ध की मौत हुई है। वन विभाग की टीम भी मौके पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि, किसी भी ग्रामीण के द्वारा जंगली जानवर को देखे जाने की बात सामने नहीं आई है। - सुरेंद्र नाथ तिवारी, एसपी सिटी

स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही ने ली दो की जिंदगी, बाइक सवारों को मारी टक्कर; मौके पर तोड़ा दम

गांव धनकोट के नजदीक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इसके बाद एक बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि बुजुर्ग की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई।

गुरुग्राम। गांव धनकोट के नजदीक रविवार देर शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इसके बाद एक बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि बुजुर्ग की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई।

सड़क पार कर रहे बुजुर्ग की पहचान धनकोट में ही बने एक आश्रम में रह रहे जगतलाल के रूप में की गई। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गांव हरीपुर के रहने वाले थे। बाइक सवार की पहचान राजस्थान के अलवर जिले में गांव तिसमर के रहने वाले आरिफ के रूप में की गई। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में नूंह जिले में गांव अगोन के रहने वाले मौसम ने बताया कि वह एक निजी कंपनी के माकड़ौला प्लांट में काम करते हैं। उनके साथ ही आरिफ काम करते थे। दोनों अपनी-अपनी बाइक से धनकोट की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान एक ठेके नजदीक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी।

इसके बाद आरिफ की बाइक में सीधी टक्कर मार दी। इससे आरिक की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही से दो लोगों की मौत हुई है। बता दें कि जिले में प्रतिदिन से चार से पांच सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हो रही हैं। इसके बाद भी चालक नियंत्रण में वाहन चलाने को तैयार नहीं। इस साल दो महीने के दौरान 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर वाहनों की चपेट में नहीं आएंगे वन्य जीव, पुलियों की सफाई हुई शुरू

वन्य जीव गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर वाहनों की चपेट में नहीं आएंगे। इसके लिए जहां भी रोड में पुलिया है उसकी सफाई शुरू कर दी गई है। सफाई होने के बाद सभी पुलिया के ऊपर फेंसिंग कराई जाएगी।

गुरुग्राम। वन्य जीव गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर वाहनों की चपेट में नहीं आएंगे। इसके लिए जहां भी रोड में पुलिया है, उसकी सफाई शुरू कर दी गई है। सफाई होने के बाद सभी पुलिया के ऊपर फेंसिंग कराई जाएगी। इससे वन्य जीव रोड पार करने की बजाय पुलिया से होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा-आ सकेंगे। इससे पहले मानेसर घाटी में दिल्ली-जयपुर हाईवे की पुलिया को साफ किया गया था। पुलिया के ऊपर फेंसिंग भी कराई जा चुकी है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड अरावली पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। बंधवाड़ी और मांगर बनी इलाके में रोड के दोनों तरफ काफी घनी हरियाली है। इसमें काफी संख्या में वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीव रोड पार करते रहते हैं। कई साल पहले एक तेंदुआ वाहन की चपेट में आ गया था।

आगे से वन्य जीव वाहनों की चपेट में न आएं, इसे ध्यान में रखकर अरावली पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों में जहां भी पुलिया (वाइल्ड लाइफ कारिडोर) है, उसे साफ करने पर वन विभाग की वन्य जीव शाखा जोर दे रही है। पहले मानेसर घाटी में पुलिया की सफाई कराई गई। अब गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर काम शुरू किया गया है। कुल आठ पुलिया हैं। जिनकी सफाई होनी हैं। कुछ की सफाई हो चुकी है।

वन विभाग का मानना है कि क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि वन्य जीव विचरण करते हुए कई बार अरावली के नजदीक के रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं। तीन महीने पहले डीएलएफ फेज-एक इलाके में भी तेंदुआ देखा गया था। मानेसर के आसपास अक्सर तेंदुए विचरण करते हुए दिख जाते हैं।

पिछले महीने ही एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक दो तेंदुए दिखे थे। बता दें कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों में अधिकतर वन्य जीव रहते हैं। इन इलाकों में बंधवाड़ी, मांगर बनी, मानेसर घाटी, दमदमा, मंडावर, भोंडसी, सांप की नगली, ग्वालपहाड़ी, शिकोहपुर और फिरोजपुर झिरका शामिल हैं।

अरावली में वन्य जीव

गीदड़- 166
लकड़बग्घा- 126
सेहली- 91
बिज्जू- 61
नेवला- 50
तेंदुआ- 31
जंगली बिल्ली- 26
लोमड़ी- 4
भेड़िया- 3
लंगूर की प्रजाति- 2

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के दोनों तरफ अरावली पहाड़ी क्षेत्र में काफी संख्या में वन्य जीव हैं। इसे देखते हुए जहां भी पुलिया है, उसकी सफाई कराई जा रही है। सभी पुलिया के ऊपर फेंसिंग भी कराई जाएगी। - एमएस मलिक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)

इनसाइड

परिवार की सुरक्षा से न करें खेलवाड़, कार लेने से पहले जरूर चेक करें ये 5 सेफ्टी फीचर्स

अगर आप इन दिनों एक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। किसी भी कार में इन टॉप-5 सुरक्षा फीचरों को जरूर होना चाहिए।

नईदिल्ली। हम में से ज्यादातर लोग जब कभी भी नई कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस और सुरक्षा से जुड़े फीचर्स पर ध्यान देते हैं। पहले जहां कार के डिजाइन, लुक और पावरट्रेन को भारत में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब ग्राहक इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं कि उनकी कार हर तरह से सुरक्षित रहें और चालक के साथ-साथ पैसेंजर को भी सुरक्षा पहुंचाए। सेफ्टी फीचर्स के लिए लोग अधिक से अधिक रकम चुकाने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि, बहुत कम लोगों को पता होता है कि असल में उनकी गाड़ी पर कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए। इसलिए, आज हम आपको 5 ऐसे सेफ्टी कार फीचर्स (Safety Car Featurers) के बारे में बताएंगे जिनका होना बेहद जरूरी है।

1. एयरबैग (Airbags)

कार चाहे सस्ती हो या महंगी, उसमें एयरबैग का होना बेहद जरूरी है। यह दुर्घटना के समय एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को कम करता है और चालक के साथ-साथ पैसेंजर की जान को भी बचाता है। वर्तमान में भारत में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियों में डुअल एयरबैग होता है, लेकिन अब सरकार ने 6 एयरबैग का होना कार में जरूरी कर दिया है।

2. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)

आजकल की गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर EBD के साथ ABS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ABS या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अचानक ब्रेक लगाने पर कार को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी के पहिये लॉक हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए ABS बहुत मददगार साबित होता है।

3. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC)

ओवरस्टेयर या अंडरस्टेयर के कारण कई बार कार अपना नियंत्रण खो देती। इससे बचने के लिए आपात स्थिति के दौरान ईएससी ब्रेक लगाता है और इंजन की पावर को संतुलित करता है।

4. एडजस्टेबल स्टीयरिंग

बहुत बार स्टीयरिंग व्हील और चालक के बीच की दूरी और ऊंचाई सही नहीं रहने के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, जो बाद में जाकर दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इस वजह से एडजस्टेबल स्टीयरिंग का कार में होना बेहद जरूरी है। यह ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील की ऊंचाई और ड्राइवर से दूरी को ठीक रखने में मदद करता है।

5. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

बेहतर कंट्रोल और ईंधन की बचत के लिए आजकल की गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को लगाया जाता है। यह कार के हर पहिये पर लगा होता है जो कि एक सेंसर के जरिए डैशबोर्ड तक सूचनाओं को भेजता

हीरो जल्द शुरू कर सकता इलेक्ट्रिक बाइक पर काम, अमेरिका की इस बड़ी कंपनी से मिलाया हाथ

दोपहिया प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प ने सोमवार को कहा कि उसने प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को डेवलप करने के लिए अमेरिका स्थित जीरो मोटरसाइकिल के साथ एक समझौता किया है। कंपनी जल्द ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आने को तैयार है।

देश में इस समय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिमांड होना शुरू हो गया है। हालांकि, अभी इस सेगमेंट में कई स्टॉर्टअप्स कंपनियां अपना लक आजमा रही हैं। अब हीरो भी अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी ने अमेरिका के एक प्रसिद्ध कंपनी के साथ हाथ मिलाया है।

हीरो ने किया करार

दोपहिया प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प ने सोमवार को कहा कि उसने प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को डेवलप करने के लिए अमेरिका स्थित जीरो मोटरसाइकिल के साथ एक समझौता किया है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के मैन्यूफैक्चरिंग, सोर्सिंग और मार्केटिंग के पैमाने के साथ पावर ट्रेन और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डेवलप करने में जीरो के साथ समझौता किया है। सितंबर 2022 में, हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड ने कैलिफोर्निया स्थित जीरो मोटरसाइकिल में 60 मिलियन अमरीकी डालर तक के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और पावरट्रेन में बड़ा प्लेयर है।

Hero Vida की खासियत

नया हीरो वीडा वी 1 दो वेरिएंट प्लस और प्रो में उपलब्ध है। इसमें कई राइड़िग मोड इको, राइड, स्पोर्ट है। प्लस और प्रो वेरिएंट के लिए 0-40 किमी प्रति घंटे का समय लगता है वहीं क्रमशः 3.4 सेकंड और 3.2 सेकंड है। दोनों में ली- आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। प्रो वेरिएंट 3.94 kWh बैटरी पैक के साथ आता है जबकि प्लस वर्जन में 3.44 kWh बैटरी पैक मिलता है। वहीं बड़े बैटरी पैक के साथ, प्रो वेरिएंट को 165km की IDC प्रमाणित रेंज मिलती है। दूसरी ओर, प्लस वेरिएंट को 143 किमी की प्रमाणित सीमा मिलती है। फास्ट चार्जिंग स्पीड 1.2 किमी प्रति मिनट है।

Volkswagen 2025 तक लॉन्च कर सकती है अपनी हैचबैक इलेक्ट्रिक कार, एंट्री लेवल से ईवी में प्रवेश करेगी कंपनी

यह कई फॉक्सवैगन आर-बैज वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी जिसे ऑटोमेकर वर्तमान में डेवलप कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मन कार ब्रांड ने पहले पुष्टि की थी कि हर नया आर प्रोडक्ट 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा।

फॉक्सवैगन इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफी तेजी से काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी आने वाले समय में एंट्री लेवल ईवी (ID.2.) कोडनेम को डेवलप करने की तैयारी कर रही है। ब्रिटिश ऑटोमोटिव प्रकाशन Autocar UK का दावा है कि EV एक हैचबैक अवतार में आएगी, जबकि एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर भी होगी। अधिक दिलचस्प बात यह है कि EV AWD से लैस एक R-बैज प्रदर्शन-केंद्रित संस्करण के साथ आएगा, जो 300 हॉर्स पॉवर जेनरेट करने में सक्षम होगा।

जानिए इसपर क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फॉक्सवैगन ID.2 2025 की दूसरी छमाही में आएगी, और इसका आर-बैज संस्करण Abarth 500e जैसे गाड़ियों को सीधा चैलेंज करेगी। यह कई फॉक्सवैगन आर-बैज वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी, जिसे ऑटोमेकर वर्तमान में डेवलप कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मन कार ब्रांड ने पहले पुष्टि की थी कि हर नया आर प्रोडक्ट 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। यह इलेक्ट्रिक कार कब लॉन्च होगी, क्या कुछ इसमें खास मिलने वाला है? लुक और डिजाइन में कैसी होगी इन तमाम सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा, जब कंपनी खुद से रिवील करेगी। हालांकि, भारत में ये इलेक्ट्रिक कार आएगी या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

ईवी की तेजी से बढ़ रही बिक्री

2022 की चौथी तिमाही में फॉक्सवैगन ने वैश्विक स्तर पर 118,000 ईवी बेचे, जर्मन ब्रांड के लिए एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। कुल मिलाकर, 2022 में 300,000 से अधिक फॉक्सवैगन ईवी का उत्पादन किया गया था।

इंडियन मार्केट में कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स क्यों फेमस? असल वजहों के बारे में समझें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां बेचे गए कुल वाहनों की अधिकांश बिक्री पैसेंजर वाहनों द्वारा कवर की जाती है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों का हैं। कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स को लोग अधिक महत्व देते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इस समय कारों की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। आप खुद ही आप पास के घरों में खड़ी कारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि, जिनके भी घर कार होगी उनके घर दोपहिया वाहन जरूर देखने को मिलेगा। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं उन 3 वजहों के बारे में जहां आपको यह पता चलेगा कि कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स इंडियन मार्केट में क्यों फेमस हैं

बेहतरीन माइलेज

कारों की तुलना में मोटरसाइकिल की माइलेज भी अधिक होती है। अगर कार औसतन 25 की माइलेज देती है तो टू-व्हीलर भी 60-70 तक की औसतन माइलेज देने में सक्षम है। यही वजह है कि भारत में अधिकतर लोग चार पहिया की तुलना में दोपहिया वाहन खरीदना अधिक पसंद करते हैं। इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आने वाली मोटरसाइकिलों जिसमें अधिक सीसी का इंजन लगा हुआ होता है उसकी औसतन माइलेज 20-30 Kmpl होती है।

प्रदूषण

पर्यावरण के नजरिए से भी दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन की तुलना में बेहतरीन होते हैं, क्योंकि चार पहिया वाहन अधिक ईंधन खाते हैं और उससे अधिक पॉल्यूशन भी निकलता है, वहीं दोपहिया वाहन हैं बहुत कम ईंधन खर्च होने के कारण उससे होने वाली पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है। इसलिए, पर्यावरण के लिहाज से टू-व्हीलर बेस्ट होती हैं।

किफायती दाम

दोपहिया वाहन कार की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं। जिस वजह से एक मध्यम वर्गीय परिवार और निचला मध्यम वर्गीय परिवार भी इसे खरीद पाता है। भारत के बाज़ार में लगभग 40,000 रुपए की शुरुआती क़ीमत से दोपहिया वाहनों की बिक्री शुरू हो जाती है। इसके अलावा, इन वाहनों के लिए बीमा बहुत कम लागत पर आता है। दोपहिया वाहनों की सबसे ख़ास बात यह होती है कि इनकी री सेल क़ीमत भी बहुत अधिक होती है। साथ ही इनका माईलेज भी कार की तुलना में कहीं बेहतर होता है।

इस मौसम में सबसे अधिक परेशान करती है कार के अंदर की धुंध, इन उपायों से मिलेगा चुटकियों में समाधान

आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। इससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

नई दिल्ली। इस समय ठंड काफी तेजी से बढ़ रही है।सुबह के समय कोहरा काफी अधिक हो रहा है, जिससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये परेशानी कार के अंदर भी होती है। अगर आपके कार के अंदर भी ठंड के मौसम में धुंध भर जाती है तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। सबसे अधिक दिक्कत इस समय होती है। कोहरे के कारण आप कार के बाहर का देख नहीं सकते हैं। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें

अगर आप इस बात से अनजान हैं तो अपनी कार के अंदर आप विंडशील्ड को डिफॉग करने के लिए गाड़ी के अंदर दिए गए डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें। ये बटन आपके कार के अंदर आता है। इसको दबाने के बाद हवा सीधे विंडशील्ड तक पहुंच जाती है।

एसी को ऑन करें

कार में जैसे ही बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद फॉग महसूस होने लगता है, जिसके कारण आप बाहर का देख नहीं सकते और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आप कार में एसी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद लिंट-फ्री कपड़े से स्क्रीन को पोछ लेना चाहिए, ताकि आपको दिखाई देने लगे। इसके कारण कार के अंदर की धुंध भी गायब हो जाती है।

खिड़की को नीचे करें

कार के अंदर से धुंध को बाहर करने के लिए खिड़की को नीचे करना एक अच्छा ऑप्शन है। इससे बाहर की हवा अचानक आपकी कार के अंदरुनी हिस्सो को भर देती है, इसके कारण ही अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तरह हो जाता है।

चीन से आयात पर अंकुश का परिदृश्य

डा. जयंतीलाल भंडारी

> साथ ही देश के उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) का अधिकतम लाभ लेते हुए इसके कारगर क्रियान्वयन से चीन से आयातों का प्रभुत्व कम करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। इससे चीन से आयात कम होंगे। चीन को निर्यात बढ़ेंगे और चीन से व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकेगी।

हाल ही में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 7 मार्च को एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कार्यक्रम में कहा कि जल्द ही चीन से आयात होने वाले घटिया स्तर के 2000 उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही चीन से सस्ता माल मंगाना आसान नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए बड़े पैमाने पर गुणवत्ता मानक का नियम लागू होगा। निःसंदेह इस समय जब चीन से हर तरह का आयात बढ़ रहा है और चीन से देश का व्यापार असंतुलन चिंताजनक स्तर पर है, तब सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे चीन से आयात पर अंकुश लगेगा। गौरतलब है कि इस समय चीन से लगातार बढ़ता व्यापार असंतुलन पूरे देश की एक बड़ी आर्थिक चिंता का कारण बन गया है और इस पर पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर विचार मंथन हो रहा है। पिछले माह 23 फरवरी को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में कहा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सीधे तौर पर देश का उद्योग-कारोबार और देश की कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कलपुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में अपने प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। साथ ही देश की बड़ी कंपनियां शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में भी बहुत पीछे हैं। विगत 17 फरवरी को वाणिज्य मंत्रालय ने भारत-चीन व्यापार के वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 10 महीनों के आयात-निर्यात के जो नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक इन 10 महीनों की अवधि में चीन से किए जाने वाले आयात में 9 फीसदी का उछाल आया है, जबकि इस अवधि में चीन को किए जाने वाले निर्यात में 34 फीसदी की भारी कमी आई है।

वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 10 महीनों में भारत के द्वारा किए जाने वाले कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.91 फीसदी है। भारत ने 10 महीनों में कुल 83.76 अरब डॉलर का आयात चीन से किया है, जबकि इसी अवधि में भारत ने चीन को केवल 12.20 अरब डॉलर का निर्यात किया है। भारत द्वारा किए जाने निर्यात में चीन की हिस्सेदारी केवल 3.30 फीसदी है। स्थिति यह है कि इस समय जहां दुनिया के 150 से अधिक देशों में भारत से किए जाने वाले निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं चीन को निर्यात में लगातार कमी का परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। यद्यपि पिछले दो सालों में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है। यहां तक कि कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं, लेकिन फिर भी व्यापार के क्षेत्र में भारत की चीन पर निर्भरता भी लगातार बढ़ी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि चीन के साथ व्यापार घाटा भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में भारत और चीन के बीच 1.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था।

लेकिन 2013-14 में ये बढ़कर 36.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रकार इसमें करीब 2346 फीसदी की वृद्धि हुई। इन वर्षों में चीन से आयात भी बढ़कर दस गुना से अधिक हो गया है। जहां इन वर्षों में पूरा देश चीन में निर्मित घटिया चीनी उत्पादों से भर गया और भारत लगातार बहुत कुछ चीनी सामानों पर निर्भर होता गया, वहीं अभी भी चीन से बढ़ता आयात चुनौती बना हुआ है। चीन से भारत में आने वाले सामान में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में काम आने वाले दवाइयों के कच्चे माल (एपीआई), दवाइयां, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रानिक सामान, पशु या वनस्पति वसा, अयस्क, लावा और राख, खनिज ईंधन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, उर्वरक, कमाना या रंगाई के अर्क, विविध रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक, कागज और पेपरबोर्ड, कपास, कपड़े, जूते, कांच और कांच के बने पदार्थ, लोहा और इस्पात, तांबा, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, विद्युत मशीनरी और फर्नीचर से संबंधित है। इन सामानों का चीन से आयात लगातार बढ़ा है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि वर्ष 2014-15 से स्वदेशी उत्पादों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करके चीन से आयात घटाने के प्रयास हुए हैं। वर्ष 2019 और 2020 में चीन से तनाव के कारण जैसे-जैसे चीन की भारत के प्रति आक्रामकता और विस्तारवादी नीति सामने आई, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के उपयोग की लहर देश भर में बढ़ती हुई दिखाई दी।

देशभर में चीनी सामान के जोरदार बहिष्कार और सरकार के द्वारा टिक टॉक सहित विभिन्न चीनी एप पर प्रतिबंध, चीनी सामान के आयात पर नियंत्रण, कई चीनी सामान पर शुल्क वृद्धि, सरकारी विभागों में चीनी उत्पादों की जगह यथासंभव स्थानीय उत्पादों के उपयोग की प्रवृत्ति को लगातार प्रोत्साहन दिए जाने से चीन के सामानों की भारत में मांग में कमी दिखाई दी हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बार-बार स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार ने स्थानीय उत्पादों की खरीदी को पहले की तुलना में अधिक समर्थन दिया। जहां वर्ष 2022 में दीपावली पर्व पर भारतीय बाजारों में चीनी उत्पादों की बिक्री में बड़ी कमी आई, वहीं मार्च 2023 में होली पर्व पर चीनी उत्पाद बाजार से लगभग गायब रहे। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्युफैक्चरिंग के तहत 24 सेक्टर को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चीन से आयात किए जाने वाले दवाई, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले दो वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपए आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल भी हुए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पीएलआई स्कीम की सफलता के कारण ही वर्ष 2022-23 में फॉर्मा उत्पादों के आयात में कमी आई है।

हम उम्मीद करें कि जिस तरह भारतीय खिलौना उद्योग ने चीन से खिलौनों के आयात में भारी कमी करके चमकीली मिसाल बनाते हुए देश और दुनिया को अचंभित किया है, उसी तरह उद्योग-कारोबार के अन्य क्षेत्रों में भी चीन से आयात घटाने और चीन को निर्यात बढ़ाने के नए अध्याय लिखे जाएंगे। हम उम्मीद करें कि चीन से घटिया स्तर के सामानों के आयात पर अंकुश लगाने से चीन के साथ देश के व्यापार असंतुलन में कमी आएगी। हम उम्मीद करें कि एक बार फिर से देश के करोड़ों लोग चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही देश के बाजार में चीन के बढ़े हुए वर्चस्व को तोडऩे के लिए पूरे देश में और अधिक उद्यमी और कारोबारी शोध और नवाचार तथा नए आइडिए को अपनाते हुए, चीनी कच्चे माल और चीन से संबंधित अन्य आयातित सामानों के स्थानीय विकल्प प्रस्तुत करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथ ही देश के उद्योग-कारोबार जगत के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) का अधिकतम लाभ लेते हुए इसके कारगर क्रियान्वयन से चीन से आयातों का प्रभुत्व कम करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। इससे चीन से आयात कम होंगे। चीन को निर्यात बढ़ेंगे और चीन से व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकेगी। साथ ही ऐसे में चीन पर आयात निर्भरता पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

संपादक की कलम से

भ्रष्टाचार की जांच तो होगी

विपक्ष मोदी सरकार को आईना दिखा रहा है। देशहित के कुछ मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करना चाहता है। लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखना चाहता है, लेकिन सरकार खुन्नस में आकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का घोर दुरुपयोग करने पर आमादा है। सीबीआई ने 2022 के अंत तक 124 मामले दर्ज किए थे, जिनमें 118 मामले विपक्षियों के खिलाफ दर्ज किए गए और भाजपा के मात्र 6 केस इस दायरे में लाए गए। अर्थात करीब 95 फीसदी विपक्षी आरोपित हैं और किसी भी स्तर पर जेल भेजे जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) है। उसने कांग्रेस के 24, तृणमूल के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, द्रमुक के 6, राजद और सपा के 5-5 और आम आदमी पार्टी (आप) के 3 नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज कर रखे हैं। जांच जारी है। कुछ नेता जेल में कैद हैं। विपक्ष एजेंसियों के दुरुपयोग और सरकार के नाजायज विशेषाधिकार पर चिलचिला रहा है। इसे 2024 के आम चुनाव का वृत्तांत बनाना चाहता है।

विपक्ष की लामबंदी अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। संविधान, कानून और नैतिकता का तकाजा यह है कि यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उसकी जांच जरूरी है और प्रत्येक मामले को कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट नेता, अंततः, देश की जनता को लूटते हैं और उनके भरोसे को ठगते हैं। ईडी में 51 सांसदों और 71 विधायकों के खिलाफ जांच जारी है। वे सभी विपक्ष के नहीं हैं। ये जांच एजेंसियां पहले की सरकारों के अधीन भी कार्यरत थीं, लिहाजा आज भी मौजूदा सरकार के संवैधानिक अधिकार-क्षेत्र में हैं। यदि आज इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो पहले की सरकारों ने भी 'तोता' बनाकर रखा था। यह सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी है। मामलों का कम और ज्यादा होना बेमानी है। चूंकि हमारी संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि जांच एजेंसियां, अंततः, केंद्र सरकार के ही अधीन काम करती हैं। दरअसल बुनियादी सवाल यह है कि भ्रष्टाचार किया गया है अथवा नहीं? क्या जांच-पड़ताल और छापेमारी के बिना ही एजेंसियां आरोप-पत्र अदालत में दाखिल कर सकती हैं? एजेंसियां या सरकार नहीं, बल्कि माननीय न्यायाधीश साक्ष्यों, सबूतों, दस्तावेजों और कानून की धाराओं के मुताबिक, आरोपितों को रिमांड पर भेजते हैं अथवा न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कोसना, उन्हें 'तानाशाह' करार देना या प्रत्येक भ्रष्टाचार के बदले अडानी, अडानी का लगातार प्रलाप करना नैतिक या तर्कसंगत नहीं है।

एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष के कई नेता सर्वोच्च अदालत तक दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अदालत ने भी हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। शीर्ष अदालत भी कहती रही है कि कानूनी मामला कानूनी पायदानों के जरिए ही चलना चाहिए। जनता के जनादेश ऐसे विलापों से कतई प्रभावित नहीं होते। बहरहाल ताज़ा मामला लालू यादव और उनके परिवार तथा 2004-09 के दौरान रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले का ही लें, तो जांच और एजेंसियों की छापेमारी को 'अनैतिक' या 'दुरुपयोग' कैसे करार दिया जा सकता है? लालू यादव कुख्यात चारा घोटाले में सजायाफ्ता नेता हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। यह केस प्रधानमंत्री देवगौड़ा के कार्यकाल के दौरान दर्ज किया गया था। उस सरकार के समर्थक नेता लालू भी थे। ईडी ने मौजूदा छापों के दौरान जो बरामद किया है, उसके ब्यौरे देश के सामने आ चुके हैं। कुल 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, जिसमें बेनामी संपत्ति भी बताई गई है। सवाल है कि क्या इतनी 'अमीरी' की जांच नहीं होनी चाहिए? लालू तो खुद को गरीब-गुरबे का नेता घोषित करते रहे हैं।

14 मार्च का इतिहास

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार मार्च 14 किसी वर्ष में दिन संख्या 73 है और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 74 है। भारत और विश्व इतिहास में 14 मार्च का अपना ही एक खास महत्व है, क्योकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं हैं। आईये जानते हैं 14 मार्च की ऐसी ही कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ जिन्हे जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित तथ्य ऐसे होंगे जैसे : आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आजादी, नई तकनिकी का अविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस इत्यादि।

14 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएँ विश्व में ⚡

वर्ष	घटना/वारदात/वृत्तांत
1489	साइप्रस की रानी कैथरीन कार्नारो को मजबूर होकर द्वीप के प्रशासन को वेनिस गणराज्य में बेचना पड़ा।
1653	नीदरलैंड के कमांडर जोहान वान गैलेन ने एंग्लो-डच युद्ध में ब्रिटिश बेड़े को हराया।
1728	जीन-जैकस रूसो ने पहली बार जिनेवा को छोड़ा।
1757	ब्रिटिश रॉयल नेवी एडमिरल जॉन बिंग को कोर्ट-मार्शल किया गया और फायरिंग स्क्वाड द्वारा उस पर हमला किया गया जब वह सात साल के युद्ध की शुरुआत में माइनोरका के बटलर के दौरान 'अपना कमाल ' करने में असफल रहा।
1794	एली व्हिटनी को सूती जीन के लिए पेटेंट दिया गया।
1794	अमेरिकी आविष्कारक एली व्हिटनी ने कॉटन जिन का पेटेंट कराया, जो पहली मशीन थी, जिसने कॉटन फाइबर को अपने सीडपोड्स से जल्दी और आसानी से अलग किया।
1800	कार्डिनल बार्ना चियारामोंटी पायस VII को 251वें पोप के रूप में 21 मार्च को वेनिस में ताज पहनाया गया।
1826	पनामा में दक्षिण अमेरिकी राज्यों की जनरल कांग्रेस की बैठक हुई थी।
1833	हॉब्स टेलर पहली डेंटिस्ट का जन्म हुआ।
1834	जॉन हेर्सल ने अब सितारों के खुले समूह को पता लगाया, जो अब एनजीसी 3603 के रूप में जाना जाता है, केप ऑफ गुड होप से देख सकते है।
1879	बुद्धि के धनी अलबर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ।
1885	मिकाडो, गिल्बर्ट और सुलिवन का सबसे अधिक बार प्रदर्शन किया जाने वाला ओपेरा, लंदन के सावॉय थिएटर में शुरू हुआ।
1910	केर्न काउंटी, कैलिफ़ोर्निया में तेल के भावी कर्मचारियों ने एप्रेसुराइज़्ड तेल जमा में ड्रिल किया, जिसके परिणामस्वरूप सबसे बड़ा आकस्मिक तेल स्पिलिन इतिहास है।
1915	प्रथम विश्व युद्ध-ब्रिटिश सेनाओं ने जर्मन डी एशिया स्क्वाड्रन के अंतिम अवशेष एसएमएसड्रेसडेन पर कब्जा कर लिया और मसे के ए टिएरा के चीलियन द्वीप के पास।

न्याय होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए

राजेंद्र मोहन शर्मा,
पूर्व डीआईजी

> संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जनता को जल्द न्याय मिलने के मौलिक अधिकार के तहत अदालतों की खुली कार्यवाही देखने का भी अधिकार है, मगर ऐसा अदालतें होने नहीं देती'

पुलिस एवं न्यायालय दोनों न्याय के सोपान होते हैं। पीड़ित व्यक्ति के लिए जहां पुलिस न्याय का पहला पड़ाव है, वहां न्यायालय एक आखिरी व महत्वपूर्ण आशा की किरण की तरह होता है। मगर जब दोनों पड़ावों पर असहाय व्यक्ति को वांछित सुकून न मिल पाए, तब कानून के विश्वास पर गहरी चोट लगती है। पुलिस के लिए किसी अपराधी को पकडऩा और फिर जमानत पर छोड़ देना ही काफी नहीं है, बल्कि पीड़ित के साथ सच्ची सहानुभूति रखना तथा तफतीश को सही मुकाम पर पहुंचाना और भी महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में पीड़ित व्यक्ति को इस बात का एहसास व विश्वास करवाना भी आवश्यक होता है कि अपराधियों के साथ कड़ी पूछताछ की गई है। पीड़ित व्यक्ति को कई बार इस बात का पता ही नहीं चलता और उसे बताया भी नहीं जाता है कि गवाहों का बयान क्या लिखा गया है और जघन्य अपराधों में अपराधी की जमानत न होने के लिए पुलिस ने क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। कई बार पुलिस वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है तथा अपराधियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है तथा इसी तरह केस को बिना वजह से लम्बित रखा जाता है तथा अपराधी सरेआम दनदनाते रहते हैं।

ऐसे खूंखार व बेरहम अपराधियों को बंधित नहीं करवाया जाता तथा न्याय खुले तौर पर लहुलूहान होता रहता है। पुलिस भले ही उचित व निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई कर रही हो, मगर अब भी तफतीश का पारम्परिक व वर्षों से चला हुआ रिवाज नहीं बदला जा रहा है। कई बार अपराधियों को उनके द्वारा किए गए गुनाहों के अनुरूप कानूनी दायरे में न लाकर उनसे ज्यादती या पक्षपात कर दिया जाता है। यह भी देखा गया है कि पुलिस किसी अपराधी को अपनी हिरासत में रखने के लिए न्यायालय से गुहार करती रहती है तथा हिरासत समाप्त होने के बाद अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए इस बात का वर्णन करते हुए सिफारिश की जाती है कि वह गवाहों को डरा-धमका सकता है या फिर कहीं भाग सकता है तथा जज साहिब भी पुलिस की सिफारिश को यथावत उचित मानते हुए अपराधियों को अनिश्चित समय की न्यायिक हिरासत बढ़ा देते हैं। ऐसे हालात में अपराधी को अपने जुर्म से अधिक सजा भुगतने को मजबूर कर दिया जाता है। हलांकि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 व 468 के अंतर्गत पुलिस को अपनी तफतीश की एक निश्चित परिसीमा बढ़ाने का अधिकार है, मगर फिर भी यह चाहिए कि तफतीश को कम से कम समय में पूरा करके न्यायालय में भेजा जाए। वर्ष 2010 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन किया गया तथा पुलिस को सात वर्ष की सजा से कम वाले अपराधों में मुलाजमों को जमानत पर छोडऩे के लिए अधिकारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि पुलिस आमतौर पर छोटे मोटे अपराधों में भी लोगों की जमानत नहीं होने देती थी तथा वकीलों का एक बहुत मक्कडज़ाल जमानत करवाने के लिए ऐसे अपराधियों से मनचाहे पैसे वसूलते रहते थे। उदाहरणतः पति या ससुराल वालों द्वारा किसी महिला का उत्पीडऩ किए जाने पर 498.।

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुक्कदमा दर्ज किया जाता, मगर इस में कुल सजा दो वर्ष तक ही है तथा अपराधियों को पुलिस अपने ही स्तर पर जमानत दे सकती है, मगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस कोई न कोई बहाना बनाकर कोर्ट से जमानत नहीं होने देती। इस सम्बन्ध में अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य क्रिमिनल अपील नंबर 1277 वर्ष 2014 का हवाला देना उचित है। जिसके अनुसार पुलिस ने निचली अदालत में सांठगांठ करके अपराधियों को जमानत न देकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया था। इस अपील में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारी व सम्बन्धित जज के विरुद्ध कंटैप्ट आफ कोर्ट का निर्णय देकर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जज को तो परमात्मा का रूप माना जाता है क्योंकि वह किसी की जिन्दगी ले भी सकता और दे भी सकता है। संविधान ने उन्हें अपार शक्तियां प्रदान की हैं, जिनका उपयोग वे अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं, मगर शायद पद की नजाकत की वजह से कई बार कुछ जज साहिब विवेक का सही व पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते तथा पीडित/अपराधी दोनों को उचित समय पर न्याय नहीं मिल पाता। कुछ जज किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी होते हैं तथा अपने पद की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। न्याय न सिर्फ होना चाहिए मगर दिखना भी चाहिए, यह उक्ति महान रोमन सम्राट जुलियस सीजर के इस व्यक्तव्य से ली गई है कि उसकी पत्नी न केवल सन्देह रहित बल्कि सन्देह से ऊपर होनी चाहिए। यह बात उसने तब कही थी जब उसे पता लगा कि उसकी पत्नी पोम्पिया के सम्बन्ध कलोडियस नामक व्यक्ति से हो गए हैं तथा उसने इसी संशय के आधार पर उसे तल्लाक दे दिया था।

उसने कहा था कि जो लोग उच्च पद पर सुशोभित हुए होते हैं उन्हें थोड़ा भी अनौचित्य व अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए तथा यदि वे ऐसा कर बैठते हैं तो उन्हें अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए। इस व्यक्तव्य से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि उच्च पदों पर तैनात व्यक्तियों का आचरण बिल्कुल सन्देह से परे होना चाहिए तथा वे आम लोगों के रक्षक व पालक होने चाहिए। न्यायिक सिद्धान्त में अक्सर यह कहा जाता है कि चाहे सौ गुनहगार छूट जाएं, मगर किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि जज की यह जिम्मेदारी है कि किसी निर्दोष को सजा न हो, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई गुनहगार सजा से बचकर जा न पाए। यह दोनों ही बातें सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कई बार ट्रायल कोर्ट सबूतों का परीक्षण भी सही ढंग से नहीं कर पाते तथा किसी एक गवाह द्वारा सही बयान न दिए जाने पर अन्य सभी गवाहों के तर्कसगंत बयानों को नजरअन्दाज करते हुए अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जनता को जल्द न्याय मिलने के मौलिक अधिकार के तहत अदालतों की खुली कार्यवाही देखने का भी अधिकार है, मगर ऐसा हमारी अदालतें होने नहीं देती। यदि अदालतों की कार्यवाही का सीधी प्रसारण हो जाए तो देश में करोड़ों लोगों को जल्द समय पर न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। इससे न्यायिक अनुशासन में बढ़ौतरी होगी तथा फिर पता चलेगा कि मामलों का स्थगन क्यों और कितनी बार किया गया।

बाज़ारवाद के इस दौर में ग्राहक राजा नहीं बल्कि गुलाम बन चुका है

डॉ. नीलम महेंद्र

> यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए (ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए) ये कंपनियां मार्केटिंग और पब्लिसिटी का इस हद तक सहारा ले रही हैं कि आज एडवरटाइजिंग अपने आप में एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग बन चुका है।

आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो है बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद का दौर। अब पहला प्रश्न यह कि इसका क्या मतलब हुआ? परिभाषा के हिसाब से यदि इसका अर्थ किया जाए तो वो ये होगा कि आज उपभोक्ता (यानी किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाला) ही राजा है। खास बात यह है कि बाज़ारवाद के इस दौर में उपभोगता की जरूरत से आगे बढ़कर उसके आराम को केंद्र में रखकर ही वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है।

मोबाइल है तो यूजर फ्रेंडली। कोई ऐप है तो उसका इस्तेमाल करने वाले की उम्र यानी बच्चे, युवा, अथवा वयस्क के मानसिक विकास, उसकी जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसे कस्टमर फ्रेंड्ली बनाया जा रहा है। अगर रोबोट है तो ह्यूमन फ्रेंड्ली। और पूंजीवाद के इस युग में तो मनुष्य के उपभोग के लिए सामान बनाने वाली विभिन्न कंपनियां उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए (ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए) ये कंपनियां मार्केटिंग और पब्लिसिटी का इस हद तक सहारा ले रही हैं कि आज एडवरटाइजिंग अपने आप में एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग बन चुका है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि इसके क्या मायने हैं? नहीं वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि पूंजीवाद के इस दौर में आप यानी ग्राहक एक राजा हैं। ये तो हमें एक ग्राहक के रूप में एहसास कराया जा रहा है लेकिन सत्य इसका उलट है। सत्य तो यह है कि उपभोगतावाद के इस दौर में हम बाज़ारवाद के गुलाम बनकर रह गए हैं। क्यों चौंक गए न ?

चलिए जरा खुल कर बात करते हैं, इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। सच बताइए जब हमारा बच्चा घर की रोटी या दाल चावल या सब्जी के बजाए मैग्गी की जिद करता है और हम यह जानते हुए कि हमारे बच्चे की सेहत के लिए मैगी ठीक नहीं है फिर भी हम मैगी खरीदते ही नहीं हैं बल्कि उसे खाने भी देते हैं तो क्या हम अपने मर्जी के राजा बनकर खरीदते हैं?

नहीं नहीं ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि जरा गहराई और ईमानदारी से विषय पर सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे की जिद के आगे नतमस्तक हो रहे हैं तो माफ कीजिएगा आप गलत हैं। उस कंपनी ने आपके बच्चे को माध्यम बनाकर आपको अपना उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर दिया।

यह तो एक उदाहरण है। सोचेंगे तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने ही उदाहरण हमें मिल जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी-सी नहीं है कि उपभोक्तावाद के इस दौर में हमारी खाने पीने की आदतें प्रभावित हो रही हैं। बात इससे काफी आगे बढ़ चुकी है।

क्योंकि बात अब एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर, पर एक समाज के तौर पर हमारे मूल्यों, हमारी नैतिकता, हमारे व्यक्तित्व, हमारे आदर्शों के कभी ₹कूलर₹ बनने के नाम पर तो कभी ₹चिल आउटर₹ के नाम, पर कभी ₹अपने लिए जीने₹ के नाम पर तो कभी ₹हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ₹ के नाम पर हमारे विचारों के प्रभावित होने तक पहुंच गई है।

परिणामस्वरूप सदियों से चली आ रही हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना के मूल विचार भी प्रभावित होने लगे हैं। क्योंकि बाज़ारवाद के इस दौर में हम एक उपभोक्ता के रूप में उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए पैसा कमाने का एक साधन मात्र हैं। एक बच्चे के रूप में, एक युवा के रूप में, एक पुरुष के रूप में एक महिला के रूप में एक बुजुर्ग के रूप में हम उनके लिए एक टारगेट कस्टमर से अधिक कुछ नहीं हैं। अपने लक्ज़री उत्पादों को बेचने के लिए किसी समाज को विलासिता की ओर आकर्षित करना बाज़ारवाद की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। कोई आश्चर्य नहीं आज इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलन में हैं कि "हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ₹ या ₹मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ मुझे वैसे ही स्वीकार करो₹।

आज की पीढ़ी तो इन वाक्यों के प्रति आकर्षित भी होती है और सहमत भी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो बाज़ारवाद अपने भौतिक सुखों को देने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें ₹ये दिल मांगे मोर₹ या ₹डर के आगे जीत है₹ जैसे संघर्षशील बनने का जज्बा देता है, वो ही बाज़ारवाद जब बात हमारे व्यक्तित्व के विकास की आती है, हमारे नैतिक उत्थान की आती है, हमारे भीतर पारिवारिक या सामाजिक मूल्यों के विकास की आती है तो जो ₹मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसा ही स्वीकार करो₹ या फिर ₹मैं एक साधारण मनुष्य हूँ भगवान नहीं₹ जैसे विचार परोस देता है। वो बाज़ारवाद जब बच्चों और माँ से सम्बंधित कोई उत्पाद बेचता है तो अपने विज्ञापन में महिला को एक ₹परफेक्ट मॉम₹ से लेकर ₹सुपर मॉम₹ तक के रूप में दर्शाता है लेकिन वही बाज़ारवाद जब अपना कोई विलासितापूर्ण उत्पाद बेचता है तो महिला के लिए ₹हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ₹ या फिर ₹इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्टर₹ का विचार देता है। अब आप कहेंगे कि इन वाक्यों में क्या दिक्कत है। इन वाक्यों में दिक्कत ये है कि ये वाक्य अधूरे हैं और अधूरे वाक्यों के रिक्त स्थान को हर कोई अपने हिसाब से भरने के लिए स्वतंत्र है। वैसे भी कहते हैं कि ज्ञान के न होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि अधूरे ज्ञान होने से होता है। इन वाक्यों के साथ भी यही हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व में आप किसी भी देश या संस्कृति में देखें तो हम पाएंगे कि एक मानव के रूप में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति निरंतर अपने उत्थान अपनी तरक्की की सोचता है। वो अपनी पूरी जीवन यात्रा में रोज कुछ नया सीखता है और आगे बढ़ता है। सोशल स्टेटस की बात हो या भौतिक सुखों की, मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है। घर बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए लेकिन जब व्यक्तित्व के विकास की बात आए, नैतिक मूल्यों के विकास की बात आए तो इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट! बात जब व्यक्तिगत या पारिवारिक या फिर सामाजिक मूल्यों की आए तो मैं भगवान नहीं इंसान हूँ!

ब्रीफ न्यूज

बाजार में 'हिंडनबर्ग इफेक्ट', उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा, निफ्टी लाल निशान पर बंद

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में जारी उठा-पटक जारी है। गुरुवार के कारोबारी सेशन में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224.16 अंकों की बढ़त के साथ 59,932.24 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 5.90 अंकों की गिरावट के साथ 17610.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 156 अंकों की मजबूती के साथ 40669 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। गुरुवार को बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 27 फीसदी की गिरावट के साथ 1565 रुपये के स्तर पर बंद हुए। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में यह 1495 रुपये तक फिसला। यह कंपनी के पिछले 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर है। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट का बड़ा कारण सिटी ग्रुप की तरफ से लिया गया फैसला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिटी ग्रुप ने अदाणी सिक्योरिटीज के मार्जिन लोन पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे पहले क्रेडिट सुईस ने अदाणी समूह के बॉन्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके बाद सिटी ग्रुप के फैसले की खबरें आईं। इन खबरों के बाद अदाणी समूह के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा और अधिकतर स्टॉक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। बजट 2023-24 में सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद आईटीसी के शेयरों में करीब 5 फीसदी की तेजी दिखी। गुरुवार को यह 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

बायजू ने करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कंपनी ने बताई छंटनी की यह बड़ी वजह

नई दिल्ली। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एडटेक यूनिकॉर्न बायजू ने करीब 1,500 कर्मचारियों की छंटनी की है। छंटनी ने मुख्य रूप से डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन कार्यक्षेत्र से कर्मचारियों को प्रभावित किया है। अक्तूबर में बायजू ने करीब 2,500 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जो उसके कार्यबल का 5 फीसदी था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बायजू के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायजू रवींद्रन ने अक्तूबर में कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि नियोजित 2,500 कर्मचारियों से आगे कोई छंटनी नहीं की जाएगी। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर केयर, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस और अन्य क्षेत्रों में कुछ कार्यों को आउटसोर्स करने की योजना बना रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, प्रबंधन मौजूदा कर्मचारियों के जाने से पहले नए भागीदारों को लाना चाहता था। छंटनी अब हुई है। उन्होंने कहा, अभी कंपनी कर्मचारियों के साथ ज्यादातर संवाद व्हाट्सएप के माध्यम से कर रही है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह बात कम लीक हो... कंपनी ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद हमें सेवरेंस पैकेज का आश्वासन दिया है। टाइगर ग्लोबल समर्थित एडटेक यूनिकॉर्न की ताजा छंटनी ऐसे समय में हुई है, जब स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार फंडिंग की कमी से जूझ रहा है। अकेले जनवरी 2023 के पहले दो हफ्तों में कम से कम 1500 स्टार्टअप कार्यबल ने नौकरी खो दीहै। पिछले एक साल में 22,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है। बायजू के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, इस बार वाइस प्रेसीडेंट और शीर्ष स्तर के प्रबंधक भी प्रभावित हुए हैं। जबकि हटाए गए कर्मचारियों में से अधिकांश या 95% जूनियर पदों पर हैं, ये सीनियर लेवल की भूमिकाओं का हिस्सा थे।

कौन हैं जीक्यूजी के राजीव जैन, जो अदाणी समूह में 15,446 करोड़ के शेयर खरीदकर 'संकटमोचक' बने

एनटीवी न्यूज

राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन और चीफ इंवेस्टमेंट ऑफिसर हैं। वे जीक्यूजी के लिए निवेश की रणनीति तैयार करते हैं। जीक्यूजी से पहले वे वॉनटोबेल एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुके हैं।

नई दिल्ली। अदाणी समूह के प्रमोटरों ने अमेरिका की वैश्विक इक्विटी-निवेश कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स को 15,446 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेच दी। बता दें कि बीते 24 फरवरी को अदाणी समूह के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से एक रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद समूह के सभी शेयर धराशायी हो गए थे। अब जीक्यूजी के निवेश की खबर के बाद समूह की कंपनियों ने फिर से हरे रंग में कारोबार करना शुरू कर दिया है। सोमवार को शुरुआती बढ़त के बाद अदाणी समूह के शेयरों में बिकवाली दिखी। हालांकि इस बीच एक नाम काफी चर्चा में है और वह नाम है दिग्गज निवेशक राजीव जैन का। उन्होंने जब से अदाणी समूह में एंट्री मारी है जब से समूह के शेयरों में निवेशकों की रुचि एक बार फिर बढ़ गई है।

राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन और चीफ इंवेस्टमेंट ऑफिसर हैं। वे जीक्यूजी के लिए निवेश की रणनीति तैयार करते हैं। जीक्यूजी से पहले वे वॉनटोबेल एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। पोर्टफोलियो के रूप में उन्होंने वर्ष 1994 में काम करना शुरू किया था। उनके नेतृत्व में जीक्यूजी निवेश क्षेत्र में 92 अरब डॉलर का पावरहाउस बन चुका है।

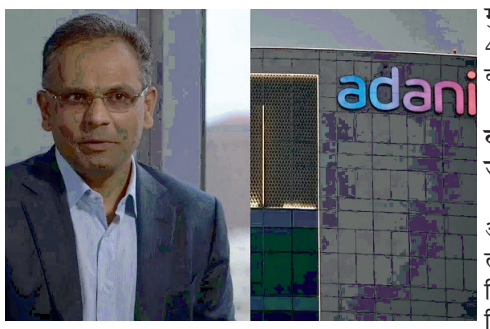

उपलब्ध: राजीव जैन

राजीव जैन ने 2016 में की थी जीक्यूजी की शुरुआत

ऐसे तो राजीव जैन का जन्म भारत में हुआ था पर वे 1990 में अमेरिका चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मियामी यूनिवर्सिटी में एमबीए करने के लिए दाखिला लिया। साल 1994 में उन्होंने वॉनटोबेल ज्वाइन किया। 2002 तक वे कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन गए। वर्ष 2016 में उन्होंने जीक्यूजी की शुरुआत की। उनके अगुवाई में वॉनटोबेल इमर्जिंग मार्केट ने दस वर्ष में 70 फीसदी तक का रिटर्न देने की उपलब्धि हासिल की। यह एमएससीआई के इमर्जिंग बाजारों से जुड़े फंड्स का लगभग दोगुना है। जीक्यूजी ने वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में अपना आईपीओ लॉन्च किया और 893 मिलियन डॉलर की रकम जुटाई।

अदाणी समूह के पास बढ़िया असेट्स और वे शानदार वैल्यूऐशन पर

बीते हफ्ते गुरुवार को अदाणी समूह की ओर से बताया गया कि जीक्यूजी ने 15446 करोड़ रुपये का निवेश कर अदाणी समूह की चार कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद से अदाणी समूह के शेयरों में बढ़िया मजबूती दिखी। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू से बातचीत में राजीव जैन ने कहा कि अदाणी समूह के पास शानदार असेट्स हैं और उससे भी बढ़िया ये हैं कि वे बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। बीते पांच वर्षों से उनकी नजर समूह के शेयरों पर थी पर तब वे महंगे थे। राजीव जैन ने भरोसा जताया है कि समूह में उनका निवेश सकारात्मक साबित होगा। जैन के मुताबिक भारत में 25 फीसदी एयर ट्रैफिक अदाणी समूह की ओर से संचालित हवाई अड्डों से गुजरते हैं। कार्गो वॉल्यूम में भी 25 से 40 फीसदी तक अदाणी समूह की कंपनी अदाणी पोर्ट्स की हिस्सेदारी है।

तेल, तंबाकू और बैंकिंग जैसे कारोबार पर दांव लगाते हैं राजीव जैन

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, राजीव जैन जीक्यूजी की लॉन्ग-ओनली इक्विटी रणनीतियों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर और एक विश्लेषक के रूप में भी काम करते हैं। उनके अधिकांश सफल निवेश दांव तेल, तंबाकू और बैंकिंग जैसे पारंपरिक व्यावसायों में हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज पर जीक्यूजी की फाइलिंग के अनुसार, जहां यह अक्टूबर 2021 में लिस्ट हुआ था, जैन के पास कंपनी की 69% हिस्सेदारी है जिसका मूल्य लगभग 2 अरब डॉलर है।

राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन और चीफ इंवेस्टमेंट ऑफिसर हैं। वे जीक्यूजी के लिए निवेश की रणनीति तैयार करते हैं। जीक्यूजी से पहले वे वॉनटोबेल एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। पोर्टफोलियो के रूप में उन्होंने वर्ष 1994 में काम करना शुरू किया था। उनके नेतृत्व में जीक्यूजी निवेश क्षेत्र में 92 अरब डॉलर का पावरहाउस बन चुका है।

सोना 25 रुपये मजबूत हुआ, चांदी की कीमतें 160 रुपये उछलीं

नई दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 25 रुपये की तेजी के साथ 55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 160 रुपये की तेजी के साथ 65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। विदेशी बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 25 रुपये की तेजी के साथ 55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 55,875 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी भी 160 रुपये की तेजी के साथ 65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, "दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव 25 रुपये की तेजी के साथ 55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक बाजारों में सोना और चांदी दोनों तेजी के साथ क्रमशः 1856 डॉलर प्रति औंस और 21.24 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार करते दिखे।

घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 460 अंक उछला, निफ्टी 17700 के पार पहुंचा

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार से सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन हरे निशान पर करोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 198.07 अंकों की बढ़त के साथ 60,007.04 अंकों के लेवल पर खुला है। शुरुआती कारोंबार में यह 385.3 अंकों के लेवल तक उछलता दिख रहा है।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों का हाल

फिलहाल सेंसेक्स 565.18 अंकों की बढ़त के साथ 60,374.15 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 174.30 अंकों की बढ़त के साथ 17,768.65 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अदाणी समूह के सभी शेयरों में तेजी दिख रही है। नायका के के शेयर दो प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सोमवार को बाजार की तेजी में आईटी सेक्टर के शेयरों का योगदान रहा। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है।

होली पर सस्ते हुए खाद्य तेल! मांग में तेजी के बावजूद खाने के तेलों की कीमतों में आ रही गिरावट

नई दिल्ली। खाने के तेल में फरवरी में 10 फीसदी तक गिरावट देखी गई है। जबकि सालभर में यह 30 फीसदी तक सस्ते हुए हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों सरसों तेल 165 से 170 रुपये लीटर बिक रहा था, जो अब घटकर 135 से 140 रुपये लीटर बिक रहा है... आम लोगों को होली के त्योहार पर खाद्य तेलों की महंगाई से राहत मिल रही है। मांग में तेजी के बावजूद खाने की तेलों के दामों पर गिरावट देखी जा रही है। खाद्य तेलों के सस्ते होने की वजह विदेशी बाजार में इनके दाम घटने के साथ ही घरेलू तिलहन की पैदावार ज्यादा होना मानी बताई जा रही है।

खाने के तेल में फरवरी में 10 फीसदी तक गिरावट देखी गई है। जबकि सालभर में यह 30 फीसदी तक सस्ते हुए हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों सरसों तेल 165 से 170 रुपये लीटर बिक रहा था, जो अब घटकर 135 से 140 रुपये लीटर बिक रहा है। इसी तरह साल भर में रिफाइंड सोयाबीन तेल के दाम 140-145 रुपये से घटकर 115 से 120 रुपये लीटर और सूरजमुखी तेल के दाम 135-140 रुपये से घटकर 115 से 120 रुपये लीटर रह गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो महीने भर में सरसों तेल 10 फीसदी, सोयाबीन तेल 3 फीसदी सस्ता हुआ है। साल भर में आयातित तेलों में कच्चे पाम तेल के दाम करीब 30 फीसदी गिरकर 95 रुपये लीटर और आरबीडी पामोलीन के दाम करीब 25 फीसदी घटकर 100 रुपये प्रति लीटर रह गए हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि होली पर खाद्य तेलों की मांग बढ़ने के बावजूद इनके दाम घट रहे हैं। क्योंकि देश में तिलहन की बंपर पैदावार होने का अनुमान है और विदेशी बाजारों में भी खाद्य तेल सस्ते हैं। दरअसल, भारत में खाद्य तेलों के दाम काफी हद तक विदेशी बाजारों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि देश में इनकी खपत की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात किए जाते हैं। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी संघ से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि ब्राजील व अर्जेंटीना में सोयाबीन और मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। जिससे विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नरम पड़े हैं। इससे देश में आयातित तेल सस्ते हुए हैं। इसके अलावा देश में खरीफ सीजन में सोयाबीन की पैदावार ज्यादा थी। अब रबी सीजन में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। लिहाजा देश में तिलहन पैदावार बढ़ने से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी का माहौल बना है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में निकाले 9,600 करोड़, महंगा है भारतीय बाजार

एफपीआई ने जनवरी में कुल 28,852 करोड़ रुपये की निकासी बाजार से की थी। पिछले सात महीने में किसी एक माह में यह सर्वाधिक निकासी थी। दिसंबर में इन्होंने 11,119 करोड़ और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ने चालू माह में 10 फरवरी तक शेयर बाजार से 9,600 करोड़ रुपये निकाले हैं। भारतीय बाजार का मूल्यांकन अन्य बाजारों की तुलना में महंगा है। इसलिए विदेशी निवेशक इन पैसों को दूसरे उभरते बाजारों में लगा रहे हैं। हालांकि, डेट बाजारों में इन्होंने 2,154 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने जनवरी में कुल 28,852 करोड़ रुपये की निकासी बाजार से की थी। पिछले सात महीने में किसी एक माह में यह सर्वाधिक निकासी थी। दिसंबर में इन्होंने 11,119 करोड़ और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विश्लेषकों का मानना है कि आगे चलकर विदेशी निवेशकों का रुझान उतार-चढ़ाव का रहेगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में लगातार छठीं बार वृद्धि की है। जब तक अदाणी समूह के मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं आती है, तब तक विदेशी निवेशकों का यह रुझान बना रहेगा।

28,852 करोड़ रुपये की जनवरी में हुई थी शेयर बाजार से निकासी

विदेशी निवेशकों ने वित्तीय सेवाओं के सेगमेंट से ज्यादा निकासी की है। हालांकि, ऑटो और कलपुर्जों वाले सेगमेंट में निवेश किया है। आईटी में जनवरी में इन निवेशकों ने बिकवाली की थी। लेकिन इस महीने इसमें खरीदारी किए हैं।

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश पर कर लगाने की तैयारी

आयकर विभाग अप्रवासी निवेशकों पर कर लगाने के मकसद से गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का पता लगाने के लिए आयकर कानून के तहत संशोधित मूल्यांकन नियम जारी कर सकता है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस संशोधन की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि आयकर अधिनियम व फेमा कानून में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के एफएमवी की गणना के लिए अलग-अलग तरीके हैं। आयकर अधिनियम के नियम 11यूए को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को (फेमा) के अनुरूप बनाने के लिए हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फिर निर्धारित किया जाएगा। 11यूए अचल संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के एफएमवी के निर्धारण से जुड़ा है।

श्रमिकों को राहत देने के मसले पर दक्षिण कोरिया और जापान के बीच समझौता

नई दिल्ली। 2018 में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जापान के निप्पॉन स्टील और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री को 100 मिलियन कोरियन वोन (77 हजार डॉलर) मुआवजे के तौर पर साउथ कोरिया के 15 पीड़ितों में प्रत्येक को दिया जाना चाहिए। यह मामला 1910 से 1940 के बीच कोरियाई लोगों को जापान की ओर से प्रताड़ित करने का है।

दक्षिण कोरिया और जापान ने सोमवार को कोरिया पर कब्जे के दौरान जापान की ओर से जबरन श्रम लिए जाने के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी देश भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ रही अशांति के मद्देनजर संबंधों को सुचारू बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे "अमेरिका के दो करीबी सहयोगियों के बीच सहयोग और साझेदारी का एक नया अध्याय बताया।

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन ने सोमवार को कहा कि इंपीरियल जापान की ओर से 15 पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा देगा।

2018 में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जापान के निप्पॉन स्टील और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री को 100 मिलियन कोरियन वोन (77 हजार डॉलर) मुआवजे के तौर पर साउथ कोरिया के 15 पीड़ितों में प्रत्येक को दिया जाना चाहिए। यह मामला 1910 से 1940 के बीच कोरियाई लोगों जापान की ओर से प्रताड़ित करने का है।

बता दें कि मुकदमे में जिन 15 पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया गया उनमें से वर्तमान में केवल तीन लोग जीवित हैं। वे सभी 90 वर्ष से अधिक के हैं।

जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने संवाददाताओं से कहा, 'हम जापान और दक्षिण कोरिया के बीच स्वस्थ संबंध बहाल करने के लिए दक्षिण कोरिया सरकार की ओर से आज घोषित उपायों का स्वागत करते हैं। यह संबंध 2018 में दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बहुत मुश्किल स्थिति में रहा है।' उन्होंने कहा, 'दक्षिण कोरिया सरकार की ओर से घोषित उपाय इस आधार पर नहीं हैं कि जापानी कंपनियां फाउंडेशन (दक्षिण कोरिया में) में योगदान देंगी। जापान और विदेशों में व्यक्तियों या निजी कंपनियों की ओर से स्वैच्छिक दान पर जापानी सरकार का कोई विशेष नियंत्रण नहीं है। जापान दक्षिण कोरियाई अदालत के 2018 के फैसले से सहमत नहीं था और टोक्यो की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया, जापान ने मेमोरी चिप्स में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। दक्षिण कोरिया ने वर्तमान दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल के पूर्ववर्ती मून जे-इन के कार्यकाल के दौरान टोक्यो के साथ अपने सैन्य खुफिया-साझाकरण समझौते को रद्द कर दिया गया था।

IMF से डील के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से मदद की आस, विश्व बैंक से मिलने वाली राशि भी अधर में

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर के वित्तपोषण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसे वैश्विक ऋणदाता ने तब तक के लिए रोक कर रखा है जब तक कि सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेकर उन्हें लागू नहीं किया जा सकता

नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आईएमएफ के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौते (एसएलए) पर हस्ताक्षर करने के लिए विश्व बैंक और एआईआईबी से दो अरब डॉलर की अतिरिक्त जमा राशि और 950 मिलियन डॉलर का ऋण हासिल करने के लिए सऊदी अरब की मदद मांग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इससे संबंधित दावे किए गए हैं।

पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर के वित्तपोषण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसे वैश्विक ऋणदाता ने तब तक के लिए रोक कर रखा है जब तक कि सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेकर उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है।

समाचार पत्र 'द न्यूज इंटरनेशनल' की खबर के अनुसार आईएमएफ से जुड़े एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने सऊदी अरब से जमा राशि और विश्व बैंक से कर्ज पर आश्वासन मिलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा हमें इसकी उम्मीद है।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार विश्व बैंक के रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी (राइज-II) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से जुड़े 950 मिलियन डॉलर के कर्ज को भी तभी मंजूरी दी जाएगी जब पाकिस्तान आईएमएफ से बेलआउट हासिल कर लेगा।

एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नकदी संकट से जूझ रहा देश अगले कुछ दिनों में वैश्विक ऋणदाता के साथ बहुप्रतीक्षित समझौते पर पहुंचने की उम्मीद कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती शत्रुता के कारण पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ बातचीत में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अर्थव्यवस्था और कूटनीति को इस तरह से चलाने के लिए एक नाजुक संतुलन कार्य में कर्मचारी स्तर के समझौते (एसएलए) को सुरक्षित करना है जो इस्लामाबाद के व्यापक हित के अनुकूल हो।'

पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पिछले सप्ताह कहा था कि इस्लामाबाद को अपने सदाबहार सहयोगी चीन से 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे ताकि तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके।

फिर खुली पाकिस्तान की पोल: 'सीमापार से नहीं कम हुआ आतंकवाद, दुष्प्रचार कर रहा पड़ोसी', MEA रिपोर्ट में खुलासा

एनटीवी न्यूज

भारत लगातार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी घुसपैठ को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन का मुद्दा उठाता रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को जारी रखे हुए है।

नई दिल्ली। भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया वैसे तो पहले से ही जगजाहिर है अब भारतीय विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ने भी पड़ोसी देश की हरकतों की पोल खोल दी है। दरअसल, आज यानी सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जारी की है। इसमें मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही इसमें 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में इस्लामाबाद द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की गंभीरता ना दिखाने की बात भी कही गई है।

भारत के खिलाफ मनगढ़ंत प्रचार में लगा पाकिस्तान

2022 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने और अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रचार करने में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर पाकिस्तान के सभी कार्यों और बयानों को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सभी देशों के बीच एक बड़ी समझ है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इससे जुड़े मामले देश के आंतरिक हैं।

26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपियों को सजा देने से बच रहा पाकिस्तान

अपनी सालाना रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के परिवारों को न्याय दिलाने में अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। वह इसे लटकाए रहने की रणनीति में लगा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लगातार यह कहने कि पाकिस्तान 2004 की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे और अपनी जमीन या क्षेत्र का भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न करने दे, सीमा-पार से आतंकवाद, घुसपैठ और भारत में एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा में हथियारों की अवैध तस्करी में कोई कमी नहीं आई है।

भारत का सामान्य पड़ोसी संबंधों पर जोर

इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है। भारत का हमेशा यह प्रयास रहा है कि आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल की बजाय मुद्दों को द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। भारत लगातार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी घुसपैठ को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन का मुद्दा उठाता रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को जारी रखे हुए है।

पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता, गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा की

एनटीवी न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आगामी गर्मियों के मद्देनजर गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएमओ के मुताबिक, पीएम मोदी को मानसून के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तैयारी, आपदा प्रबंधन, अस्पतालों में आग से सुरक्षा उपायों और जंगल की आग से निपटने के लिए तैयारी के बारे में जानकारी दी गई।

पीएम मोदी ने आईएमडी से दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने को कहा, जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। उसे आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की संभावित उपज के बारे में भी बताया गया। बैठक में सिंचाई जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीवी समाचार चैनल और एफएम रेडियो दैनिक मौसम के पूर्वानुमान को समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट दे सकते हैं। पीएम मोदी ने सभी अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर बल दिया। उन्हें गर्मी से संबंधित आपदाओं की तैयारी के लिए देशभर में चल रहे विभिन्न प्रयासों और शमन उपायों के बारे में भी अपडेट किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल और क्या करें-क्या न करें को आसान भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। इसके प्रचार के जिंगल्स, फिल्म, पैम्फलेट आदि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के आग लगने से बचाव संबंधी उपायों की विस्तृत ऑडिट की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अग्निशमन विभाग की ओर से सभी अस्पतालों में मॉक फायर ड्रिल किया जाना चाहिए। पीएमओ ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार करने के लिए कहा गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव और एनडीएमए के सदस्य सचिव ने भाग लिया।

समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, अगली तारीख 18 अप्रैल तय की

केंद्र ने कोर्ट से समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों में कटौती नहीं करने का आग्रह किया। केंद्र ने कहा कि इस फैसले का पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दिए जाने के अनुरोध वाली याचिकाओं को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। पांच जजों की पीठ मामले पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों से जुड़ा है। इनका एक-दूसरे पर प्रभाव है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्यार, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही बरकरार है और कोई भी उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब शादी के अधिकार को प्रदान करना नहीं है। एसजी मेहता ने कहा कि जिस क्षण समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाएगी, गोद लेने पर सवाल उठेगा और इसलिए संसद को बच्चे के मनोविज्ञान के मुद्दे को देखना होगा। उसे जांचना होगा कि क्या इसे इस तरह से उठाया जा सकता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़े के गोद लिए हुए बच्चे का समलैंगिक होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह से संबंधित मुद्दा अहम महत्व का है। इस पर पांच-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। समलैंगिक विवाह पर पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई का सीधा प्रसारण (लाइव-स्ट्रीम) किया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट से समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों में कटौती नहीं करने का आग्रह किया। केंद्र ने कहा कि इस फैसले का पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दिए जाने के अनुरोध वाली याचिकाओं को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का केंद्र ने विरोध किया है। सरकार का दावा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना पर्सनल लॉ और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के बीच नाजुक संतुलन के पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है।

सरकार ने 2024-25 तक रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य तय किया; कोरवा प्लांट को लेकर कही यह बात

एस.टी. सेठी

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है।

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 2021-22 में निजी कंपनियों और राज्य संचालित रक्षा निर्माताओं द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य 86,078 करोड़ रुपये था, जबकि यह राशि 2020-21 में 88,631 करोड़ रुपये और 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपये थी।

उत्पादन मूल्य 2018-19 में 50,499 करोड़ रुपये और 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपये था। भट्ट ने कहा, सरकार ने वर्ष 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात सहित 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने यह भी कहा कि 2021-22 में रक्षा निर्यात का मूल्य 12,815 करोड़ रुपये था, जबकि चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक यह 13,398 करोड़ रुपये था।

एक अलग सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत योजना प्रक्रिया पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। भट्ट ने कहा कि वार्षिक अधिग्रहण योजना सेवाओं से इनपुट के आधार पर सालाना तैयार की जाती है और यह पहचाने गए खतरों और अंतर-सेवा प्राथमिकता और उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित है।

आईआरआरपीएल कर रहा कलाश्निकोव एके-203 राइफलों का उत्पादन

सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कलाश्निकोव एके-203 राइफलों का निर्माण और परीक्षण वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कोरवा में भारत और रूस के संयुक्त उद्यम में किया जा रहा है।

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आईआरआरपीएल) ने स्वदेशी असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की हैं। आईआरआरपीएल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना एके-203 राइफल्स के स्वदेशी उत्पादन के लिए किया गया है। आईआरआरपीएल ने उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्वदेशी असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू करने के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की हैं।

उन्होंने कहा, 'राइफलों का निर्माण और परीक्षण चरण चल रहा है। भट्ट ने कहा कि एके-203 राइफलों के स्वदेशीकरण से भारतीय रक्षा बलों के लिए असॉल्ट राइफलों के संबंध में आत्मनिर्भरता आएगी। भट्ट ने जिन स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है उनमें 155 मिमी आर्टिलरी गन सिस्टम 'धनुष', लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 'तेजस', सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम 'आकाश', मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन', टी-90 टैंक, टी-72 टैंक, चीता हेलीकॉप्टर और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर 'डोर्नियर डो-228' शामिल हैं।

रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने कहा कि देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों का उद्देश्य लंबे समय में आयात पर निर्भरता को कम करना है। उन्होंने कहा, "विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल खर्च के 46 फीसदी फीसदी से घटकर दिसंबर, 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 36.7 फीसदी हो गया है।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक हवाई जहाज की खरीद की लागत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। भट्ट ने कहा, इस मामले में किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए मित्र देशों (एफएफसी) के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है।

उन्होंने कहा, एफएफसी के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों का विकास, अनुसंधान एवं विकास, सह-विकास और सह-उत्पादन, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप का एकीकरण करना है।

इनसाइड

अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

नई दिल्ली। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर कहा, 'जो कर्मचारी एक सितंबर 2014 से पहले सेवा में थे और एक सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर सके हैं वे अब 3 मई 2023 को या उससे पहले ऐसा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 3 मई की समयसीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को उन कर्मचारियों को एक और बदलाव की अनुमति दी थी जो 1 सितंबर 2024 तक मौजूदा ईपीएस सदस्य रहेंगे। वे पेंशन के लिए अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत तक योगदान कर सकते हैं यदि पेंशन योग्य वेतन का 8.33 प्रतिशत प्रति माह 15,000 रुपये प्रति माह है। शीर्ष अदालत ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय दिया था। यह समय सीमा 3 मार्च, 2023 के को समाप्त होनी थी। लेकिन ईपीएफओ ने पिछले सप्ताह ही कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की प्रक्रिया शुरू की।

IMF डील से पहले करों में बढ़ोतरी बनी विक्रमसिंघे सरकार के गले की फांस, ट्रेड यूनियनों ने दी चेतावनी

श्रीलंका बीते चार सालों में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ की औपचारिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इस बेलआउट पैकेज के जरिए उसकी कोशिश अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने की है।

नई दिल्ली। श्रीलंका में आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी हासिल करने के लिए की गई करों में बढ़ोतरी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। इस टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में अधिकांश सरकारी क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों ने कर सुधारों के खिलाफ सोमवार को भी हड़ताल की। साथ ही 15 मार्च से आम हड़ताल की चेतावनी भी दी है। जिन क्षेत्रों के कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बंदरगाह भी शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, कर्ज में डूबे इस देश ने इस हालत से निपटने के लिए आर्थिक उपाय अपनाएं हैं, जिनमें कर वृद्धि, और उपयोगिता दर में वृद्धि शामिल है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा निर्धारित सुधारों का हिस्सा लागू करना बेलआउट पैकेज जारी करने के लिए जरूरी है।

शिक्षा-स्वास्थ्य और बंदरगाह क्षेत्रों के कर्मचारी कर रहे हड़ताल

रानिल विक्रमसिंघे सरकार द्वारा की गई कर वृद्धि का विरोध कर रहे कर्मचारियों में शिक्षा-स्वास्थ्य और बंदरगाह क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं। सोमवार यानी आज की जा रही हड़ताल के क्रम में डॉक्टर्स ट्रेड यूनियन ने कहा कि उसने सोमवार को द्वीप राष्ट्र के नौ में से चार प्रांतों में हड़ताल शुरू की। डॉक्टर्स ट्रेड यूनियन के प्रवक्ता डॉ चामिल विजेसिंघे ने कहा कि सरकार की नीतियों के विरोध में डॉक्टर कल सुबह 8 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि इस दौरान हम अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवाएं संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार नई कर नीति वापस ले।

वहीं, यूनिवर्सिटी टीचर्स ट्रेड यूनियन के प्रवक्ता श्यामन बन्नेहेका ने कहा कि अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। अब अधिक इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नौ मार्च को काम से दूर रहने वाले श्रमिकों के साथ औद्योगिक कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अब हम बुधवार (15 मार्च) से सामूहिक कार्रवाई के लिए अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे, जब तक कि सरकार नई कर नीति को वापस नहीं ले लेती।

वहीं, पोर्ट वर्कर्स ट्रेड यूनियन के शामल सुमनरत्ने ने कहा कि हम सरकार की इन कर वृद्धि का विरोध करते हैं। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंदरगाह के कर्मचारियों ने बंदरगाह पर 'गो स्लो' ट्रेड यूनियन कार्रवाई शुरू की है। हम 15 मार्च को इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल करने के लिए अन्य ट्रेड यूनियनों में शामिल होंगे। बंदरगाह क्षेत्र की अन्य ट्रेड यूनियनें भी इसमें शामिल हो गई हैं और इसके प्रवक्ता इंजीनियर उपाली रत्नायके ने कहा कि सोमवार से कर्मचारी केवल आपातकालीन कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 14 मार्च को आधे दिन की हड़ताल करेंगे और 15 मार्च को बड़ी हड़ताल के लिए अन्य ट्रेड यूनियनों में शामिल होंगे।

IMF की मंजूरी का इंतजार कर रहा श्रीलंका

बता दें, श्रीलंका की सरकार ने जनवरी से प्रभावी रूप से कर वृद्धि की शुरुआत की थी, सरकार ने यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बेलआउट पैकेज के लिए उनकी शर्तों के तौर पर लागू किया। श्रीलंका में ट्रेड यूनियनें और प्रोफेशनल एसोसिएशंस आम तौर पर ऊंची आय वाले वर्गों की नुमाइंदगी करती हैं। ये सभी यूनियनें हाल में की गई टैक्स बढ़ोतरी का विरोध कर रही हैं। श्रीलंका में लागू नई टैक्स नीति के मुताबिक एक लाख रुपये प्रति महीने से अधिक कमाने वाले हर व्यक्ति को टैक्स दायरे में ले आया गया है। साथ ही टैक्स की दर 36 फीसदी कर दी गई है।

गौरतलब है कि श्रीलंका बीते चार सालों में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ की औपचारिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इस बेलआउट पैकेज के जरिए उसकी कोशिश अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने की है।

श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज

श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज बकाया है, जिसमें से 28 अरब डॉलर का भुगतान 2027 तक किया जाना है। देश की स्थिति ऐसी है कि भारत ने भोजन और चिकित्सा आपूर्ति के अलावा हजारों टन डीजल और पेट्रोल भेजकर कर्ज में डूबे श्रीलंका की मदद की है। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका को भोजन, दवा, रसोई गैस और अन्य ईंधन, टॉयलेट पेपर और यहां तक की माचिस जैसी जरूरी वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ईंधन और भोजन के लिए दुकानों के बाहर घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।